वर्ष : 17 ❖ अंक : 31 ❖ पृष्ठ : 08 ❖ मूल्य : ₹ 3.00 ❖ आरएनआई सं. SIKHIN/2006/17890 ❖ www.anugamini.com

सिक्किम से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

अनुगामिनी

गंगटोक
गुरुवार, 01 सितम्बर 2022

काम नहीं केवल प्रचार करती है केंद्र सरकार : नीतीश 3

हिमाचल में कांग्रेस की 10 गारंटियां : राहुल गांधी 8

विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रही है एसडीएफ : सी.पी. शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 अगस्त । सिक्किम की सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टी ने विपक्षी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) पार्टी पर राज्य सरकार के विकास कार्यों में अड़ंगा लगाने और अपने कारनामे को छिपाने के लिए जनता के हित में लाये जा रहे ऋण वसूली विधेयक का विरोध करने का आरोप लगाया है। एसकेएम के प्रवक्ता सी.पी. शर्मा ने आज एक विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि एसकेएम एक जिम्मेदार पार्टी है और यह जनता को दिये वचन को पूरा करके ही छोड़ती है।

सी.पी. शर्मा ने कहा कि पच्चीस वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान सोई रहने वाली एसडीएफ अब एसकेएम सरकार के केवल तीन वर्षों के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को देख कर अपनी बौखलाहट छिपा रही है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान एसकेएम सरकार द्वारा पेश किये गये ऋण वसूली विधेयक का एसडीएफ ने विरोध क्यों किया? इसका कारण यह है कि वे नहीं चाहते कि उनके कार्यकाल में सिक्किम स्टेट बैंक से लिये गये ऋण वापस हो। वे उसे अपनी सम्पत्ति मान रहे हैं। यदि यह विधेयक लागू हो जाता है तो उनकी करतूतों का भंडाफोड़ हो जायेगा। यह बात जनता को समझनी चाहिये।

वहीं एसकेएम प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (गोले) द्वारा राज्य के वाहन चालकों (गुरुजी) में वाहन वितरण किये जाने की योजना का विरोध करने के लिए भी एसडीएफ को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वाहन चलाकर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले गुरुजी के स्वाभिमान रक्षा एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु मुख्यमंत्री ने यह योजना शुरू की है। लेकिन इससे एसडीएफ की नींद हराम हो गयी है। इतना ही नहीं एसडीएफ प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भी इसके विरोध में उतर आये हैं जो काफी हास्यास्पद एवं लज्जाजनक बात है।

उन्होंने कहा कि 25 वर्षों तक अवहेलित रहे गुरुजी लोगों को इन तीन वर्षों में मिले सम्मान का विरोध कर पवन चामलिंग ने समूचे राज्य के वाहन चालकों की भावना को ठेस पहुंचाई है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं।

सी.पी. शर्मा ने आगे कहा कि सत्ता के मोह में अंधे हुए पवन चामलिंग ने दिमागी संतुलन खो दिया है। वर्तमान सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों एवं बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के कार्यों को देख कर पवन चामलिंग बीच-बीच में इस प्रकार के ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। इससे उनके स्तर का पता चलता है। एसकेएम का मानना है कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जनता के बीच जितनी सुविधाएं वितरित करते हैं, उतनी ही पवन चामलिंग को रुलाई आती है।

उन्होंने कहा कि चामलिंग ने सत्ता एवं शक्ति को अपनी मुट्ठी में रखते हुए 25 वर्षों तक जनता को निचोड़ा है, लेकिन अब समय बदल गया है। अब उन्हें समझना होगा कि इतने सालों तक उन्होंने जिस डमरू बजा कर जनता को नचाया है, वह अब होने वाला नहीं है। 25 वर्षों तक युवाओं की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को पूरा न कर उन्हें राजनीतिक हथियार बनाने से पैदा हुई वितृष्णा की जिम्मेदारी एसडीएफ एवं उसके मुखिया पवन चामलिंग हो लेनी होगी।

एसकेएम प्रवक्ता के अनुसार विपक्षियों के तीव्र विरोध के बावजूद वे सिक्किम की जनता के लिए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

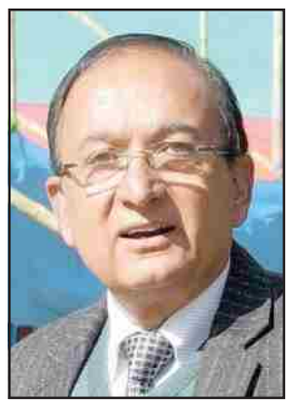

जनता के हित में राज्य के अस्पतालों में किये गये अभूतपूर्व ढांचागत विकास कार्यों के खिलाफ मूर्खतापूर्ण बयानबाजी की जा रही है। वहीं मुम्बई के कारघर में सिक्किमी जनता की सुविधा हेतु तैयार किये जा रहे सिक्किम सुस्वास्थ्य भवन को बदनाम करने की भी दुर्भाग्यपूर्ण कोशिश की जा रही है। एसकेएम पार्टी इसका खंडन करते हुए पत्रकारों से इस मानसिकता से दुखित न होने का आह्वान करती है।

संस्कृतियों के बीच आपसी संवाद महत्वपूर्ण : वेन्चुंगपा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 अगस्त । सिक्किम सरकार के खेल व युवा मामलों के अधीन स्टेट नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस सेल) द्वारा केंद्रीय खेल व युवा मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित पहले पांच दिवसीय पूर्वोत्तर एएसएस महोत्सव का आज स्थानीय मनन केंद्र में समापन हो गया।

इस अवसर पर मार्तांम रूमटेक विधायक सह डेन्जोंग एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन सोनम टी. वेन्चुंग्पा मुख्य अतिथि और खेल व युवा मामलों के सलाहकार एमएन सुब्बा सम्मानीय अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। वहीं उनके अलावा समापन समारोह में खेल व युवा मामलों के सचिव कर्मा आर बोंग्पो, निदेशक श्रीमती डोमा छिरिंग भूटिया, स्वास्थ्य निदेशक डॉ. पेमा लेप्चा के अलावा रोटरी क्लब सिक्किम, मायालु क्लब के प्रतिनिधिगण, एनएसएस स्वयंसेवक एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

यहां अपने वक्तव्य में मुख्य अतिथि सोनम टी. वेन्चुंग्पा ने विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी संवाद के बढ़ावे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश की वास्तविक ताकत युवाओं के हाथ में है और इस प्रकार का आयोजन युवाओं को बेहतर भविष्य एवं समृद्धि हेतु सशक्त बनायेगा। साथ ही उन्होंने महोत्सव में शामिल हुए सभी प्रतिभागियों एवं रिसोर्स पर्सनों दिवाकर बसनेत एवं अंजन चौधरी को धन्यवाद देते हुए इससे सम्बंधित राज्यों के प्रतिभागियों को फायदा होने की उम्मीद जतायी।

इस अवसर पर सचिव कर्मा आर बोंग्पो ने अपने वक्तव्य में देश के विकास में एनएसएस की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में जागरूकता फैलाने हेतु प्रोत्साहित किया। इस दौरान एनएसएस की स्टेट नोडल अधिकारी श्रीमती ललिता छेत्री ने भी अपना वक्तव्य रखा।

वहीं महोत्सव में सिक्किम के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली एनएसएस यूनिट की पुरस्कार मंगन जिले की काबी कालजांग ग्याछो सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, नामची जिले की केवजिंग एसएसएस, गेजिंग जिला की गेजिंग गर्ल्स सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, पाकिम जिला की पाचे एसएसएस, सोरेंग जिला की केबी लिम्बू एसएसएस तथा गंगटोक जिला की मॉडर्न एसएसएस को मिला। वहीं एनएसएस सेल, सिक्किम की ओर से खेल व युवा मामलों की निदेशक श्रीमती डोमा छिरिंग भूटिया को भी सम्मानित किया गया।

समापन समारोह में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के एनएसएस स्वयंसेवकों ने महोत्सव के दौरान हुए अपने अनुभव और प्राप्त जानकारियों को साझा किया। वहीं इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ।

राज्यपाल ने की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात

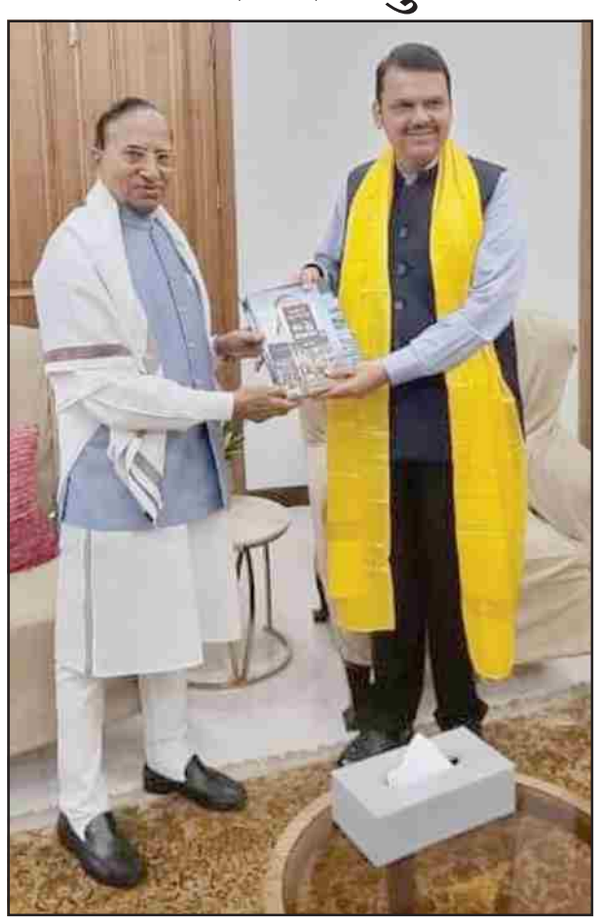

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 अगस्त । सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई स्थित उनके सरकारी आवास पर मुलाकात करते हुए। इस दौरान उन्होंने विकासमूलक विषयों पर चर्चा की तथा राज्यपाल महोदय ने उनके सकारात्मक पहल एवं प्रयास से महाराष्ट्र का अधिक से अधिक विकास होने की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।

सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की वार्षिक बैठक सम्पन्न

अनुगामिनी नि.सं.

जोरथांग, 31 अगस्त । सिक्किम कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन की 27वीं वार्षिक बैठक आज यहां प्रदेश क्षमता निर्माण संस्थान के सभागार में सम्पन्न हुई। इसमें यूनियन के उपाध्यक्ष एमजे राई, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के सचिव डॉ. पी सेंथिल कुमार, प्रधान निदेशक डॉ. बीएम छेत्री, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, सभी बोर्ड सदस्यों के अलावा यूनियन के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

यूनियन की अतिरिक्त महाप्रबंधक सुश्री केसांग के स्वागत भाषण शुरू हुई इस वार्षिक बैठक में सचिव सह प्रबंध निदेशक ने पिछले एजीएम में स्वीकृत हुए कार्यों समेत अन्य सूचनाओं की प्रस्तुति दी। साथ ही उन्होंने इस वर्ष दो एजीएम आयोजित होने की बात कहते हुए यूनियन की कार्य प्रगति पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान यूनियन की नयी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। चुनाव अधिकारी सुश्री सारदा रोका ने इसमें 17 में से 10 बोर्ड निदेशकों के बगैर प्रतिद्विद्विता के चुने जाने की जानकारी दी। वहीं 7 सीटों पर चुनाव सम्पन्न हुआ।

जानकारी के अनुसार यूनियन के नये बोर्ड निदेशकों में गंगटोक-1 से देवी प्रसाद तिमसिना, गंगटोक-2 से हर्कमान सुब्बा, पाकिम-1 से अर्जुन राई, पाकिम-2 से चन्द्र प्रसाद छेत्री, नामची-1 से लाकपा डोमा शेर्पा, नामची-2 से निर्मला बसनेत, नामची-3 से देवान राई, नामची-4 से दिल कुमारी सार्की, सोरेंग-1 से पूर्ण प्रसाद शर्मा, सोरेंग-2 से नय छिरिंग लेख्चा, सोरेंग-3 से मन बहादुर राई, सोरेंग-4 से दीनेश चन्द्र दहाल, सोरेंग-5 से डीआर शर्मा, गेजिंग-1 से पूर्ण बहादुर छेत्री, गेजिंग-2 से पुष्पा लाल छेत्री, गेजिंग-3 से पदम बहादुर छेत्री और गेजिंग-4 से यम कुमार शर्मा शामिल रहे।

बाद में कार्यक्रम में सभी विदा होने वाले बोर्ड सदस्यों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में राज्य के दुग्ध किसानों, विलेज मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटियों तथा इसके प्रबंधन को सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित बोर्ड सदस्यों का भी खादा पहना कर स्वागत किया गया।

यहां अपने वक्तव्य में एमडी ने कहा कि राज्य में दुग्ध क्षेत्र के विकास हेतु किसानों को सरकार द्वारा मुहैया करायी जाने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिये। उन्होंने किसानों से अपना उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की बात कही। वहीं इस दौरान यूनियन के वाइस चेयरमैन एमजे राई ने दुग्ध किसानों, सहकारी समितियों एवं प्रबंधन को धन्यवाद दिया।

सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

अनुगामिनी नि.सं.

सोरेंग, 31 अगस्त । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज सोरेंग डीएसी सभागार में सिक्किम आमा सशक्तिकरण योजना के जिला अधिकारियों एवं फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोरेंग के जिलाधिकारी भीम ठटाल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में एडीसी धीराज सुबेदी, एडसी-डेव गायस पेगा, एसडीएम डीआर बिस्ट, एसडीएम रंजन राई के अलावा बीडीओ, पंचायत सदस्य, कल्याण अधिकारीगण, सामाजिक कल्याण निरीक्षक एवं अन्य सम्बंधित अधिकारीगण शामिल रहे।

इस दौरान डीसी ठटाल ने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में इस योजना की शुरुआत तथा इसके कार्यान्वयन हेतु सरकार तथा विभाग की सराहना की। साथ ही उन्होंने सही लाभान्वित की पहचान कर उन तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करने को कहा। इसमें उन्होंने निचले स्तर के कर्मियों के साथ समन्वय कर योजना के सही कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा हर सम्भव सहयोग प्रदान किये जाने का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम के दौरान योजना के कार्यक्रम अधिकारी सह डब्ल्यूसीडीडी संयुक्त सचिव खेमराज भट्टाराई ने पावर ख्वॉयंट प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी प्रदान की।

उन्होंने बताया कि निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार बीस हजार रुपये की रकम दो चरणों में बैंक में जमा की जायेगी। वहीं इस दौरान एक चर्चा सत्र का भी आयोजन हुआ।

क्षतिग्रस्त पुल का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 31 अगस्त । गेजिंग के जिलाधिकारी यिस्से डी योंग्दा ने आज उत्तरे तेनजिंग हिलेरी पार्क जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग का निरीक्षण किया। मानेबुंग-देन्ताम समष्टि के उत्तरे बाजार से तेनजिंग हिलेरी पार्क जाने वाली इस सड़क के बीच का एक पुल गत 27 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश में नष्ट हो गया था। ऐसे में ग्रामीणों को हो रही परेशानी की जानकारी के बाद ही आज जिलाधिकारी ने इस सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से का मुआयना किया। वहीं समष्टि प्रभारी पूर्ण हांग सुब्बा ने भी सम्बंधित विभाग से इस सड़क की तत्काल मरम्मत हेतु आग्रह किया था।

इसके बाद आज जिला शासक योंग्दा ने इस क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्से का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ देन्ताम महकमा अधिकारी नन्दकुमार कार्की, बीडीओ बसन्त मोक्तान के अलावा विभागीय अभियंता, सह-अभियंता, विभागीय कर्मचारी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण भी थे। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने दल को अपनी समस्याएं बतायीं। उन्होंने कहा कि गत 27 अगस्त की बारिश से इलाके में व्यापक नुकसान हुआ है और उनके लिए खतरा बढ़ा है। यदि समय से इसका समाधान नहीं किया गया तो पूरी बस्ती को नुकसान पहुंच सकता है।

वहीं स्थानीय ग्रामीणों एवं पीड़ितों की बातें सुनने के बाद जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले छोटे वाहनों के आवागमन की व्यवस्था हेतु तत्काल इस सड़क को खोल दिया जायेगा। वहीं अतिरिक्त जिला शासक ने पीड़ित ग्रामीणों में तारपोलिन का वितरण भी किया।

जिले में गांजे की खेती चिंता का विषय : जिलाधिकारी

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 31 अगस्त । डिस्ट्रिक्ट नार्को कोऑर्डिनेशन (एनकॉर्ड) कमिटी की एक समीक्षा बैठक आज डीएसी सभागार में आयोजित हुई। गेजिंग जिला कलेक्टर श्रीमती यीशे डी योंग्दा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गेजिंग एडीसी, एएसपी, एसडीएम, एसएसबी की 36वीं बटालियन के डिप्टी सीओ, युकसाम एसडीएम, देन्ताम एसडीएम के अलावा शिक्षा विभाग के उप निदेशक, सीनियर वेलफेयर ऑफिसर, बागवानी विभाग के एडीओ एवं अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए।

बैठक के दौरान गेजिंग डीसी ने हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक गतिविधियों पर गहरी चिंता जाहिर करते हुए इसकी रोकथाम की दिशा में गेजिंग पुलिस विभाग की सक्रियता की सराहना की। जिले में गांजा की अवैध खेती पर चिंता जताते हुए डीसी ने उन स्थानों पर नियमित रूप से अभियान चलाने की सलाह दी। वहीं इस दौरान उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जब्त किये गये मादक पदार्थों को रखने हेतु डीएसी परिसर में अलग से एक कक्ष बनाने के बारे में दिये गये निर्देश की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में एक जगह की पहचान कर ली गयी है।

वहीं इस दौरान एडीसी गेजिंग ने जिले में 36 बटालियन एसएसबी यांग्ते के सम्बंधित अधिकारियों से की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी मांगी और उन्हें पुलिस प्रशासन के समन्वय के तहत कार्य करने एवं आमलोगों में जागरूकता हेतु कार्यक्रम चलाने को कहा। साथ ही उन्होंने (शेष पृष्ठ ०३ पर)

अरुण लिम्बू की हड़ताल नाटक : रंजना प्रधान

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 31 अगस्त । सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के अरुण लिम्बू नामक प्रवक्ता के एक दिन की हड़ताल को नाटक बताते हुए कहा है कि लिम्बू इस हड़ताल को सफल होने का ढोल पीट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदूक के जोर पर सिक्किमी समाज को आतंकित करने वाले लोग समाज को बरगला कर अपने काम का स्वयं ही श्रेय लेते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं।

एसकेएम के प्रचार-प्रसार सचिव रंजना प्रधान ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि सड़क की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर सरकार को झुका कर सड़क मरम्मत शुरू करवाने का ढोल पीटना अरुण लिम्बू का अभिनय मात्र है।

उन्होंने कहा कि तिमी नामफिंग स्थित इजम खोल्सा की सड़क की मरम्मत करने की बात अरुण लिम्बू कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने पहले ही विद्या भारती सड़क मार्ग की मरम्मत का काम आरम्भ किया है।

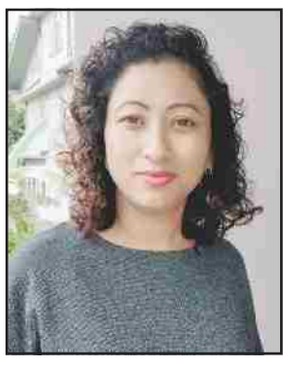

वहीं इसे लेकर अरुण लिम्बू ने पेट भर भोजन कर एक दिन की भूख हड़ताल की है। ऐसा कर वह जनता में भ्रम फैलाते हुए अपने काम का स्वयं ही श्रेय ले रहे हैं।

प्रधान के अनुसार एसडीएफ की ओर से पिछले तीन वर्षों से सड़क के बदहाल स्थिति में रहने की बात कही (शेष पृष्ठ ०३ पर)

कई बार मुझे लगता है, काश मैं राजनीति छोड़ देती : ममता बनर्जी

कोलकाता, 31 अगस्त (एजेन्सी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि कई बार उन्हें लगता है कि काश उन्होंने राजनीति छोड़ दी होती।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से कहा, 'मैंने समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया.. लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि आज की राजनीति इतनी गंदी हो जाएगी, जिस कारण मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को इतनी झूठी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, तो मैं बहुत पहले राजनीति छोड़ देती।'

मुख्यमंत्री ने उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ में हाल ही में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगर कोई उनके नाम पर संपत्ति होने या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप किए जाने का पता लगाए तो उस व्यक्ति को बुलडोजर का उपयोग करके उस संपत्ति को ध्वस्त करने की आजादी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसके लिए मेरी अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। मैंने राज्य के मुख्य सचिव से इस मामले में स्वतंत्र जांच करने के लिए कहा है। यदि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का एक भी आरोप हो, तो इसके लिए संबंधित सदस्य जवाबदेह होगा।' उन्होंने कहा, 'मैं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं रहती। वे एकल परिवार इकाइयों की तरह अलग-अलग रहते हैं। हम सामाजिक अवसरों पर मिलते हैं।'

उन्होंने विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का भी जिक्र किया कि कोयला और पशु तस्करी और शिक्षक भर्ती घोटालों जैसे वित्तीय अपराधों की आय का अंतिम गंतव्य कालीघाट है। हालांकि उन्होंने और कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री आवास की ओर था, जो कालीघाट में है।

मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप कालीघाट पर क्यों रुक रहे हैं? यदि आप में साहस है, तो उस व्यक्ति का नाम लें जो उस पैसे का अंतिम प्राप्तकर्ता है। या आपका मतलब है कि पैसा कालीघाट के प्रसिद्ध काली मंदिर में जा रहा है?'

इससे पहले दिन में, उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य में पुलिस कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने की आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने रैंक के बावजूद सभी पुलिसकर्मियों के लिए विशेष वर्दी भत्ते की घोषणा की।

सत्ता के अहंकार में डूबी बीजेपी बदले की भावना से कर रही है काम : अखिलेश

लखनऊ, 31 अगस्त (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के अहंकार में डूबी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की विपक्ष के प्रति असहिष्णुता अब बदले की भावना की कार्यवाही में बदल गई है। अखिलेश ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं है। सपा सरकार में जनहित में हुए विकास कार्यों को भाजपा सरकार प्राथमिकता से बर्बाद करती जा रही है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों में झूठे दावे और जनता को बहकाने के अलावा और कुछ नहीं है।

उन्होने कहा कि समाजवादी सरकार में लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क, गोमती रिवरफ्रंट, 1090 वूमेन पावर लाइन, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जेपीएनआईसी), कैंसर हॉस्पिटल, कन्नौज में इत्र पाकर्, उमर्दा में काऊ मिल्क प्लांट जैसी लोक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की गई थी। इनमें अधिकांश बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं। यूपी डायल 100 नम्बर अपराध नियंत्रण के लिए एक कारगर योजना थी। ऐसे ही 102 नम्बर एम्बूलेंस सेवा प्रसूताओं के लिए तथा सड़क दुर्घटना में सहायतार्थ 108 नम्बर एम्बूलेंस सेवा समाजवादी सरकार में प्रभावी ढंग से प्रारम्भ की गई थी, जिसे भाजपा सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सैफई आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिशें हो रही हैं। पहले बजट मिलने में देरी की गई, अब संविदाकर्मियों की छंटनी की जा रही है। कन्नौज के इत्र को विश्वस्तर पर बढ़ावा देने के लिए सन् 2016 में समाजवादी सरकार ने इत्र पाकर् का निर्माण किया था। 2017 में भाजपा सरकार के आते ही इत्र पाकर् का निर्माण बंद हो गया। कन्नौज का इत्र भाजपा को पसंद नहीं आया। समाजवादी सरकार के समय इजरायल के सहयोग से कन्नौज में जो एग्रीकल्चर एक्सलेंस सेंटर बना था, वह बेकार हो रहा है। अगर भाजपा सरकार राजनीतिक विद्वेष से ऊपर उठकर इसे बजट और बिजली उपलब्ध कराती तो शिमला मिर्च, टमाटर, ब्रोकली एवं अन्य सब्जियों की पौध मिलती और किसानों की आय भी बढ़ती।

देशव्यापी विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच की जाए : आतिशी

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। दिल्ली की शराब नीति को लेकर भाजपा के हमले के बाद अब आम आदमी पार्टी की विधायक और प्रवक्ता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पलटवार किया है। आप नेता आतिशी ने कहा कि आज विधायकों का प्रतिनिधिमंडल से मिलने जाएगा और देशव्यापी विधायकों की खरीद फ़रोख़्त की जांच की मांग करेगा।

विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित तौर पर चलाए जा रहे ऑपरेशन लोटस की जांच के लिए दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक बुधवार को सीबीआई निदेशक से मुलाकात करेंगे।

आप की नेता आतिशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अपराह्न तीन बजे आप के 10 विधायक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक से मुलाकात करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा ने दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ रुपये देकर पाला बदलने का प्रस्ताव दिया है।

आतिशी ने आरोप लगाया कि जब भी भाजपा किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हार जाती है तो उस राज्य की सरकार को गिराने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस्तेमाल से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत की जाती है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद सत्तारूढ़ दल के विधायकों को पैसे का प्रलोभन दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वे अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं तो उनेक विरुद्ध मामले वापस लिए जा सकते हैं। भाजपा की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है।

कर्नाटक में अपनी ही सरकार से खुश नहीं भाजपा नेता, रेप के आरोपी धर्मगुरु को लेकर पीएम मोदी को लिखेंगे चिट्ठी

बेंगलुरु, 31 अगस्त (एजेन्सी)। कर्नाटक में एक बार फिर से भाजपा के नेता अपनी ही सरकार से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। बलात्कार के आरोपी लिंगायत महंत के खिलाफ पॉक्सो मामले में ढुलमुल रवैया अपनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एच विश्वनाथ ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखेंगे।

कर्नाटक के एमएलसी ने बुधवार को कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र से भी मुलाकात की और उन्होंने आरोपी महंत मुरुघा शिवमूर्ति शरणारू के साथ-साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने को कहा था। भाजपा नेता ने कहा, 'यदि गृह मंत्री ज्ञानेंद्र को कोई शर्म है तो वह आरोपी साधु के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें। जिला प्रशासन और चित्रदुर्ग के पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।'

कर्नाटक भाजपा नेता ने कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। एमएलसी ने कहा, 'मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए सभी इनपुट के साथ एक विस्तृत पत्र लिखूंगा।'

विश्वनाथ ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी राजनीतिक नेता इस घटना के बारे में बात नहीं कर रहा है।

उन्होंने कहा, 'कोई भी राजनेता, विपक्षी नेता, सामाजिक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक अपना मुंह नहीं खोल रहा है। सब कुछ राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें वोट खोने का डर है। आप सिर्फ वोट के लिए नाबालिगों से बलात्कार के आरोपी का समर्थन कर रहे हैं। सिद्धारमैया, एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं लेकिन वे चुप हैं, पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा आरोपी का बचाव कर रहे हैं, वर्तमान सीएम मुद्दे को ठीक से नहीं संभाल रहे हैं, गृह मंत्री समर्थक की तरह बयान दे रहे हैं, क्या हो रहा है।'

कर्नाटक एमएलसी ने आगे दावा किया कि यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा, 'पॉक्सो अधिनियम एक मजबूत कानून है, और इसे 2012 में नाबालिग लड़कियों को यौन उल्लंघन से बचाने के लिए लाया गया था। इसके तहत, 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन, यहां शिकायत दर्ज होने के चार दिनों के बाद भी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बजाय उन्हें सम्मानपूर्वक उनके मठ में वापस लाया गया।'

विश्वनाथ ने यह भी कहा कि आरोपी महंत को पद छोड़ देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'आरोपी महंत को मठ महंत के पद से अस्थायी रूप से इस्तीफा देना चाहिए और नाबालिग लड़कियों और उनके परिवारों की सुरक्षा के हित में कानूनी कार्रवाई के लिए सहयोग करना चाहिए। मैं आरोपी महंत को जानता हूं, और अगर वह साफ निकलते हैं, तो समाज उनका और अधिक सम्मान करेगा।

इससे पहले मंगलवार को चित्रदुर्ग में जिला सत्र न्यायालय ने मुरुघा मठ के मुख्य महंत की अग्रिम जमानत याचिका को एक सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। नाबालिग लड़कियों द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद चित्रदुर्ग में प्रभावशाली मुरुगा मठ के महंत के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। चित्रदुर्ग में मुरुघा मठ के शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, लड़कियों के साथ दो साल से अधिक समय तक दुर्व्यवहार किया गया।

तरनतारन चर्च में तोड़फोड़, पादरी के कार को भी फूंका

अमृतसर, 31 अगस्त (एजेन्सी)। पंजाब के तरनतारन जिले के एक गांव में बुधवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित एक गांव में उपद्रवियों ने जमकर उत्पाद मचाया।

उन्होंने तीन मंजिला चर्च में तोड़फोड़ की, यही नहीं, मदर मैरी और ईसा मसीह की मूर्तियों को भी तोड़ा, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया।

बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड को बंदूक की नोक पर बंदी बनाकर पादरी की कार में भी आग लगा दी।

आग की लपटों में घिरी कार और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स मूर्ति को हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहा है।

आरोपियों की गिरफ्तारी और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की मांग को लेकर बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने ठक्करपुरा गांव में अनिश्चितकालीन धरना दिया।

यह घटना सिखों की सर्वोच्च अस्थायी सीट के प्रमुख अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक बयान जारी करने के बाद सामने आई है।

पुलिस ने बताया कि चार नकाबपोश युवक गिरजाघर में दाखिल हो गए, चौकीदार के सिर पर पिस्तौल तान दी और गिरजाघर में तोड़फोड़ करने से पहले उसके हाथ बांध दिए। उन्होंने जाने से पहले एक मूर्ति को भी तोड़ा और पादरी की कार को आग के हवाले कर दिया।

उन्होंने बताया कि घटना के बाद तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रंजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में पुलिस का एक दल स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा, तथाकथित ईसाई मिशनरी धोखे से सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। पंजाब के सिखों और हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। यह सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हालांकि कानून में धर्म के नाम पर अंधविश्वासी प्रथाओं के लिए मामला दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण कोई भी सरकार उनके (मिशनरियों) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। दो दिन पहले, निहंगों और उनके समर्थकों के एक समूह ने अमृतसर के दादुआना गांव में ईसाई मिशनरियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को बाधित कर दिया था।

ईसाइयों के एक समूह ने बुधवार को घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और खेमकरन, भीखीविंड, पत्ती, हरीके और फिरोजपुर की ओर जाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया गया है।

प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।

बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री, भारत का जलवायु संकट का समाधान करने का इरादा

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को कहा कि भारत वैश्विक उत्सर्जन के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार नहीं होने के बावजूद समस्या का समाधान करने का इरादा दिखा रहा है। यादव ने पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मामलों पर चर्चा के लिए इंडोनेशिया के बाली में जी20 देशों की मंत्री स्तरीय बैठक में कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद का वादा एक मृगतृष्णा बना हुआ है और इसकी मौजूदा गति एवं पैमाना वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाता।

उन्होंने कहा कि शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन देशों की है, जो वातावरण में संचित ग्रीनहाउस गैस सांद्रता के लिए ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, हालांकि भारत वैश्विक उत्सर्जन के लिए पारंपरिक रूप से जिम्मेदार नहीं रहा है, फिर भी हम अपने कार्यों से समस्या सुलझाने का इरादा दिखा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि भारत एक बहु-आयामी दृष्टिकोण के जरिए निम्न कार्बन उत्सर्जन करने वाले उद्योग स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत ने सभी मकानों में बिजली उपलब्ध कराने और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा तक तेजी से पहुंच बढ़ाने जैसे कदमों से हालिया वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा भारत नवीकरणीय ऊर्जा के दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उन क्षेत्रों से उत्सर्जन को कम करने के लिए अहम साबित होगा, जिनमें इसे कम करना कठिन कार्य है।

उन्होंने कहा, इन सभी प्रयासों के लिए कम लागत पर निवेश की आवश्यकता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय मदद को 2019 के स्तर से 2025 तक दोगुना करने की खातिर नवोन्मेषी मॉडल की आवश्यकता है। इसके अलवा कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियां विकसित एवं इस्तेमाल करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक असर उन गरीब एवं कमजोर देशों पर पड़ रहा है, जो जलवायु संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं और जिनके पास यथास्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, क्षमता और वित्त का अभाव है।

मंत्री ने कहा कि 2019 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दिया गया सार्वजनिक धन अनुदान के बजाय ऋण के रूप में दिया गया। उन्होंने कहा कि 2019-20 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल छह प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी गई और इससे विकासशील देश और अधिक कर्ज में डूबते जा रहे हैं। यादव ने कहा, अर्थव्यवस्था को इस तरह से प्रोत्साहित करने के लिए संसाधन जुटाने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे यह अधिक लचीली और सतत बन सके, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकसित देशों से मिल रही वित्तीय मदद की मौजूदा गति एवं पैमाना वैश्विक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाता है। दुनिया को यह समझना चाहिए कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक-दूसरे से अलग देखने के बजाय उन्हें एक साथ देखने की आवश्यकता है।

सभी को एक साथ आने की जरूरत : शरद पवार

मुंबई, 31 अगस्त (एजेन्सी)। राकांपा ने एक बार फिर विपक्षी एकता की वकालत की है। उनका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ सभी को एक साथ आना होगा। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सभी को एक साथ आने और मोदी सरकार का मुकाबला करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं।

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। भाजपा का मकसद केवल छोटे दलों को सत्ता से बाहर करना है।

उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने 2014 के आम चुनाव के समय से कई वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। आम गैर-भाजपा दलों को एक साथ लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, वह अपनी उम्र के कारण कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में आज एक बार फिर उनका विपक्षी एकता की वकालत करना नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं।

इससे पहले शरद पवार ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से मना कर दिया था। दरअसल, राष्ट्रपति चुनाव से पहले 15 जून को विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई थी। इसमें 17 राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था।

बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार हां करें तो उन्हें विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया जाएगा। शरद पवार के नाम पर पूरा विपक्ष एकजुट है। इस पर शरद पवार ने कहा था कि वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की दौड़ में नहीं हैं।

डीजीसीए ने स्पाइसजेट के दो और विमानों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को स्पाइसजेट के दो और बोइंग-737 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया। इसके साथ ही अगस्त में किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइन के छह बोइंग-737 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। स्पाइसजेट के विमानों में पिछले कुछ महीनों से लगातार कुछ न कुछ खराबी देखने को मिली हैं। यहां तक इमरजेंसी लैंडिंग भी करवानी पड़ी है।

डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, 31 अगस्त को अपरिवर्तनीय विपंजीकरण और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण (आईडीईआरए) के तहत बोइंग 737-800 विमान वीटी-एसपीयू और बोइंग 737-900ईआर विमान वीटी-एसजीक्यू का पंजीकरण रद्द किया गया है। केपटाउन संधि के तहत, अगर कोई चूक होती है, तो पट्टा देने वाले और ऋणदाता, पट्टे पर दिए गए विमान का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं। इस तरह के अनुरोध आईडीईआरए के तहत किए जाते हैं।

इसी महीने के तीसरे सप्ताह में डीजीसीए ने स्पाइसजेट के एक पायलट का लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। खराब मौसम में विमान के गंभीर रूप से हिलने-डुलने और कई यात्रियों के घायल होने की घटना के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई थी। यह घटना एक मई को हुई थी। विमान मुंबई से दुर्गापुर की उड़ान पर था। उस समय बताया गया था कि विमान के गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ के संपर्क में आने के कारण उसमें सवार 14 यात्री और चालक दल के तीन सदस्य घायल हो गए।

वहीं, विमानन कंपनी स्पाइसजेट के कर्मचारियों ने लगातार दूसरे महीने देरी से वेतन मिलने का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि उसने वेतन का भुगतान 'ग्रेड' के हिसाब से करना शुरू कर दिया है। स्पाइसजेट के कर्मचारियों ने बुधवार को दावा किया कि चालक दल के सदस्यों समेत अन्य कर्मचारियों को जुलाई महीने के लिए वेतन मिलने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अभी तक 'फॉर्म-16' भी नहीं मिला है।

जो सबसे भ्रष्ट वही 2024 में होगा विपक्ष का नेता : संजय जायसवाल

पटना, 31 अगस्त (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना सीएम केसीआर की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि जल्द ही विपक्ष के दो दर्जन तथाकथि 2024 के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होगा। उनमें से नेता यानी पीएम कैंडिडेट वही चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। वहीं, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात को विपक्षी एकता का कॉमेडी शो करार दिया है।

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि अब जाकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को बिहार आने का मौका मिला। आज वह रबर स्टैंप मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि तेलंगाना के राजपरिवार से ज्यादा भ्रष्ट बिहार के राज परिवार को बचाने के लिए बहुत-बहुत आभार। जल्द ही दो दर्जन तथाकथित 2024 के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन होगा और नेता वही चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को अपने प्रदेश में संपोषित करेगा।

इससे पहले सुशील मोदी ने कहा कि तेलंगाना सीएम केसीआर भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तरह परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनका जनाधार खिसक रहा है।

नीतीश कुमार से उनका मिलना विपक्षी एकता के कॉमेडी शो का ताजा एपिसोड होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में केसीआर अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जीता पाए थे। 2014 में लालू यादव भी अपनी बेटी को लोकसभा नहीं भेज पाए थे।

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म के दुरुपयोग के कारण मानव तस्करी के मामले बढ़े : अमृत शर्मा

अनुगामिनी नि.सं.

गेजिंग, 31 अगस्त । यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा पर एक दिवसीय कानूनी साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन सिक्किम राज्य महिला आयोग द्वारा भारत सरकार के न्याय विभाग (दिशा), कानून मंत्रालय के सहयोग से किया गया। आज का कार्यक्रम पश्चिम जिले के बर्मेक में आयोजित महात्मा श्रीजंगा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों ने भाग लिया। सामाजिक कार्यकर्ता तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के श्री अमृत शर्मा ने रिसोर्स पर्सन के रूप में पोक्सो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी और बच्चों के खिलाफ विभिन्न प्रकार के अपराध और इसके सुरक्षा तंत्र के बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्स ऐप जैसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के कारण तस्करी के मामले, साइबर अपराध और बच्चे के लापता होने के मामले बढ़े हैं। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 भी साझा किया।

केंद्र प्रशासक वन स्टॉप सेंटर सुश्री पेमा डिकी भूटिया ने रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम (रोकथाम, निषेध और निवारण) 2013 और आंतरिक शिकायत समितियों की भूमिका पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के बीच के अंतर को समझाया और इस तरह की घटनाएं होने पर रिपोर्ट करने का आग्रह किया। इसके अलावा, उन्होंने वन स्टॉप सेंटर के कामकाज और इसकी सेवाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ महिला हेल्पलाइन नंबर 181 भी साझा किया गया।

मुख्य अतिथि महिला आयोग की सदस्य श्रीमती टी डोमा भूटिया ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने में महिला आयोग की भूमिका और कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इस तरह के जागरुकता कार्यक्रम आवश्यक हैं ताकि बड़े पैमाने पर जनता को कानूनों के बारे में पता चल सके। उन्होंने आगे आग्रह किया कि लोगों को इस तरह की सूचनाओं को जमीनी स्तर और सामुदायिक स्तर पर प्रसारित करना चाहिए। उन्होंने सभा से और अधिक निवारक उपायों की दिशा में काम करने की भी अपील की ताकि इस तरह के अपराध न हों। कार्यक्रम का संचालन श्री सौरव खाटी और धन्यवाद ज्ञापन आदित्य छेत्री द्वारा किया गया।

जिले में गांजे की .....

शिक्षा विभाग हरेक स्कूलों में मादक विरोधी क्लबों को सक्रिय करने एवं मासिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी। इसके अलावा एएसपी गेजिंग ने जिले में हाल ही में हुए एसएडीए केस की मौजूदा स्थिति के बारे में सूचित किया। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

अरुण लिम्बू की .....

जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि तीन महीने पहले ही पहाड़ से चट्टानों के गिरने से यह सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। उन्होंने कहा कि अरूण लिम्बू के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद सरकार ने सड़क का काम शुरू नहीं किया, बल्कि सरकार के काम शुरू करने के बाद वह दिखावटी भूख हड़ताल पर बैठे थे। एसकेएम प्रवक्ता के अनुसार एसडीएफ के इस प्रकार के झूठे कार्यों के कारण ही जनता ने 2019 में उन्हें सत्ता से बेदखल किया है।

हमें सीबीआई के पॉलिटिकल कैरेक्टर से दिक्कत, बीजेपी के बदले का उपकरण बन गईं एजेंसियां : तेजस्वी

'जिस नेता ने बीजेपी ज्वॉइन की, वो पवित्र हो गया'

पटना, 31 अगस्त (का.सं.)। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि उनकी सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसी के अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है। वे बस इन एजेंसियों के पॉलिटिकल कैरेक्टर का विरोध कर रहे हैं। 8 सालों में जांच एजेंसियों को बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनीतिक बदले का एक उपकरण बना लिया है। अब तक सीबीआई, ईडी, आईटी विभाग ने सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही छापे मारे, जबकि बीजेपी के सैकड़ों विधायक-सांसदों पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई।

तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक के बाद एक ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 8 सालों में जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बना दिया है। 8 साल पहले देशवासियों ने इनकी इंटेग्रिटी और कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल कभी नहीं उठाए थे। अभी हमारा सीबीआई से विरोध इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि इनकी राजनीति से प्रेरित कार्यप्रणाली से है।

तेजस्वी ने कहा कि जांच एजेंसियां केवल विपक्ष शासित राज्य और वहां के नेताओं पर छापे मारकर अपने राजनीतिक मालिकों को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। बीजेपी के लगभग 300 से ऊपर एमपी और 1000 से अधिक विधायकों पर इन एजेंसियों द्वारा आज तक कोई रेड नहीं पड़ी। इसलिए इनके पॉलिटिकल कैरेक्टर से हमारा विरोध है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि बीते 8 सालों में विपक्ष के कई नेताओं पर इसी सीबीआई/ईडी/आईटी के माध्यम से छापे पड़े। ढेर सारे आरोप तय हुए, गोदी मीडिया के माध्यम से चरित्रहनन हुआ लेकिन जैसे ही उन कथित भ्रष्ट विपक्षी नेताओं ने बीजेपी ज्वॉइन की वो पवित्रता का प्रमाण पत्र पा गए। कोई मंत्री बन गया तो कोई मुख्यमंत्री बन गया।

बता दें कि हाल ही में लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसके बाद तेजस्वी यादव लगातार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा में सीबीआई, ईडी और आईटी को बीजेपी का जमाई तक करार दे दिया था। साथ ही रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों पर गरीबों से मारपीट के आरोप भी लगाए।

मिलकर बैठे हैं, महफ़िल में जुगनू सारे... नीतीश कुमार-केसीआर और तेजस्वी की मुलाकात पर बीजेपी का तंज

पटना, 31 अगस्त (का.सं.)। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विपक्ष को एकजुट करने के इरादे से बिहार आए तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को लेकर बिहार बीजेपी ने निशाना साधा है। बिहार बीजेपी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें केसीआर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ बैठे हुए हैं। इसके ऊपर कैप्शन में बीजेपी ने लिखा है कि "मिलकर बैठे हैं, महफ़िल में जुगनू सारे, ऐलान ये है कि सूरज को हटाया जाए।

दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कई सालों से गैर-कांग्रेसी गैर-भाजपा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे राव ने कहा- अब हमें भाजपा मुक्त भारत की जरूरत है। केसीआर ने इस दौरान कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना चाहिए और भाजपा मुक्त भारत का नारा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए केसीआर ने कहा कि हमारी ये मुहिम अबतक उड़ान नहीं भर पाई है लेकिन हमें भरोसा है कि नीतीश कुमार इसे आवश्यक गति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि उनके दिमाग में बड़ी तस्वीर है।

गौरतलब है कि नीतीश कुमार के बीजेपी छोड़कर जाने के बाद से विपक्षी खेमे में उत्साह का माहौल है। कई लोगों को उम्मीद है कि आठ बार के मुख्यमंत्री 2024 के आम चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं। बीजेपी भी नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के कारण गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद केसीआर पहले प्रमुख विपक्षी नेता हैं जिन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है।

काम नहीं केवल प्रचार करती है केंद्र सरकार : नीतीश कुमार

पटना, 31 अगस्त (का.सं.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश में कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ प्रचार हो रहा है। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें कोई काम नहीं करना है, उन्हें दूसरों का काम भी नहीं दिखता है। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिजनों और हैदराबाद दुर्घटना में मृत मजदूरों के परिजनों को तेलंगना सरकार द्वारा मुआवजा राशि दिए जाने के मौके पर मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह दर्जा नहीं दिया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता है यहां और तेजी से विकास होता।

तेलंगाना सरकार की ओर से शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख और मजदूरों के परिजनों को पांच-पांच लाख का चेक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना सीएम चन्द्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से दिया।

सीएम चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना के विकास में बिहार के मजदूर एक प्रतिनिधि के रूप में भागीदार है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार से जब भी जो क्रांति आई है देश में शांति आई है।

बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर दोनों मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे।

विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को करेंगे देश से विदा : केसीआर

पटना, 31 अगस्त (का.सं.)। बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनावों में विपक्ष को एकजुट करने के मुद्दे पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत और भाजपा को देश से विदा करने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। केसीआर ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि भाजपा सरकार से देश का हर आदमी परेशान है। लोगों के ऊपर सरकार अलग अलग टैक्स के नाम पर अत्याचार कर रही है। विकास के नाम पर सरकार केवल छलावा कर रही है।

केसीआर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसी भी क्षेत्र का विकास भाजपा सरकार में नहीं हुआ है। डॉलर के मुकाबले में रुपया लगातार गिरा है। देश की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

केसीआर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में की राजधानी दिल्ली में पानी खरीदना पड़ता है। ऐसी हालत आज भी क्यों बनी हुई है। आजादी के 75 साल हो जाने के बावजूद इन समस्याओं को हल नहीं किया गया।

तेलंगाना सरकार की ओर से गलवान शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख और मजदूरों के परिजनों को पांच-पांच लाख का चेक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना सीएम चन्द्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से दिया।

निष्पक्ष होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव : मनीष तिवारी

राजेश अलख

नई दिल्ली, 31 अगस्त । कांग्रेस सांसदों मनीष तिवारी, शशि थरूर और कार्ति चिदंबरम ने पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी निर्वाचक मंडल (डेलीगेट) की सूची सार्वजनिक नहीं किये जाने पर वस्तुत: सवाल खड़े करते हुए बुधवार को कहा कि चुनाव से संबंधित पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। तिवारी ने कहा कि निर्वाचक मंडल की सूची पार्टी की वेबसाइट पर डाली जाए। दूसरी तरफ, मिस्त्री ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है तथा निर्वाचक मंडल की सूची को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन उम्मीदवारों को यह उपलब्ध करा दी जाएगी।

लोकसभा सदस्य तिवारी ने ट्वीट किया, 'मधुसूदन मिस्त्री जी से पूरे सम्मान से पूछना चाहता हूं कि निर्वाचन सूची के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हुए बिना निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कैसे हो सकता है? निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का आधार यही है कि प्रतिनिधियों के नाम और पते कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट पर पारदर्शी तरीके से प्रकाशित होने चाहिए।' कांग्रेस के जी 23' समूह में शामिल रहे तिवारी ने कहा, यह 28 प्रदेश कांग्रेस कमेटी और आठ क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का चुनाव नहीं है। कोई क्यों पीसीसी के कार्यालय जाकर पता करे कि प्रतिनिधि कौन हैं? सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा क्लब के चुनाव में भी नहीं होता।'' उन्होंने कहा, 'मैं आपसे (मिस्त्री से) आग्रह करता हूं कि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सूची प्रकाशित की जाए।'

तिवारी ने कहा कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और यह नहीं जानता कि प्रतिनिधि कौन हैं तो वह नामांकन कैसे करेगा क्योंकि उसे 10 कांग्रेस प्रतिनिधियों की बतौर प्रस्तावक जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि 10 प्रस्तावक नहीं होंगे तो नामांकन खारिज हो जाएगा। उधर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बारे में विचार कर रहे पार्टी सांसद शशि शरूर ने तिवारी से सहमति जताते हुए कहा कि हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन मतदान कर सकता है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन सूची को लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर मनीष ने इसके लिए पूछा है तो मुझे भरोसा है कि हर कोई इससे सहमत होगा। हर किसी को जानना चाहिए कि कौन नामित कर सकता है और कौन मतदान कर सकता है।''

कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी तिवारी की राय का समर्थन किया और कहा कि हर चुनाव के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्वाचक मंडल होना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, हर चुनाव में सही ढंग से परिभाषित और स्पष्ट निर्वाचक मंडल होना चाहिए। निर्वाचक मंडल तय करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट, सही ढंग से परिभाषित और पारदर्शी होनी चाहिए। अनौपचारिक निर्वाचक मंडल कोई निर्वाचक मंडल नहीं होता।'' कार्ति चिदंबरम ने कहा, हर क्षेत्र में प्राइमरी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए परिभाषित और पारदर्शी सदस्य सूची जरूरी है। आज हम सदस्यों की संख्या का दावा करते हैं, लेकिन किसी ने इसे सत्यापित नहीं किया है।''

तिवारी और कुछ अन्य नेताओं की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर मिस्त्री ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा कि सार्वजनिक करने से इन लोगों का क्या मतलब है? सभी लोग तो कांग्रेस के संगठन चुनाव में मतदाता नहीं हैं। कांग्रेस के वोटर तो वे हैं जो प्रतिनिधि (डेलीगेट) हैं...हर पीसीसी के पास इनके नाम हैं। वे फोन करके ले सकते हैं।'' उन्होंने कहा, इस सूची को सार्वजनिक करने का कोई मतलब नहीं है। यह जनता से जुड़ा विषय नहीं है। यह कांग्रेस का विषय है। अगर हमारा कोई नेता सवाल उठाता है तो उसे फोन पर बता देता हूं कि क्या स्थिति है।'' कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 24 सितंबर से नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और यदि एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को मतदान होगा।

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 01:00 PM

DEAR TORSA MORNING

WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:92 DrawDate on:31/08/22

1st Prize ₹1 Crore/- 90K 97743

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 97743 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

01544 10768 14010 20950 26828 30254 30305 73502 85835 94644

3rd Prize ₹450/-

0113 1291 1371 2643 3228 3429 4830 5413 6204 8059

4th Prize ₹250/-

0863 2413 3350 3444 4463 4963 6552 7124 7918 8474

5th Prize ₹120/-

0005 0105 0300 0592 0665 0666 0699 0824 1016 1031
1226 1276 1351 1375 1488 1594 1632 1691 1702 1808
1930 2040 2214 2253 2286 2347 2377 2395 2404 2691
2716 3352 3388 3422 3471 3482 3605 3625 3700 3713
3796 4192 4359 4387 4500 4532 4534 4669 4932 5102
5237 5306 5420 5534 5576 5824 5873 5977 6156 6237
6310 6327 6371 6436 6498 6500 6622 6661 6664 6671
6692 6743 6766 7072 7111 7279 7323 7395 7625 7673
7680 7711 8068 8069 8335 8349 8443 8487 8505 8548
8554 8626 8870 9165 9284 9302 9337 9354 9376 9525

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 06:00 PM

DEAR MERCURY WEDNESDAY

WEEKLY LOTTERY

Draw No:92 DrawDate on:31/08/22

1st Prize ₹1 Crore/- 81K 13988

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 13988 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

10638 31046 31218 43010 46184 53391 65092 75156 78616 86566

3rd Prize ₹450/-

0173 0537 1159 2344 2787 3231 3317 3864 6378 8072

4th Prize ₹250/-

0813 1356 4179 5126 7879 7951 8092 8955 9383 9974

5th Prize ₹120/-

0174 0185 0279 0462 0508 0721 0737 0751 1023 1042
1071 1191 1219 1321 1325 1382 1456 1570 1931 2029
2330 2483 2750 2817 2915 2941 2952 2974 2977 3166
3181 3189 3480 3727 3731 3790 3887 3916 3946 4043
4206 4239 4294 4315 4470 4589 4696 4861 4880 4932
5017 5053 5089 5349 5497 5505 5506 5570 5705 5746
5855 5891 5986 6164 6341 6382 6433 6659 6842 6853
7156 7198 7216 7240 7304 7342 7366 7437 7477 7537
7547 7577 7657 7658 7677 7695 7980 8079 8094 8754
9053 9076 9318 9377 9425 9494 9524 9558 9906 9913

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

NAGALAND STATE LOTTERIES

Draw Time: 08:00 PM

DEAR EAGLE EVENING

WEDNESDAY WEEKLY LOTTERY

Draw No:192 DrawDate on:31/08/22

1st Prize ₹1 Crore/- 81C 10775

(Including Super Prize Amt)

Cons. Prize ₹1000/- 10775 (REMAINING ALL SERIALS)

2nd Prize ₹9000/-

00109 05543 16939 24964 30816 35849 37609 74421 76886 99739

3rd Prize ₹450/-

0743 1657 2017 2865 3631 5544 5842 6738 7116 8816

4th Prize ₹250/-

1048 2335 2994 3335 4390 4625 6588 7564 8901 9159

5th Prize ₹120/-

0019 0111 0208 0217 0357 0696 0717 0749 0789 0855
0964 0979 0980 1282 1508 1520 1608 1996 2052 2145
2288 2295 2366 2435 2564 3048 3145 3148 3182 3213
3218 3259 3318 3339 3383 3486 3558 3656 3720 3733
3852 3975 4150 4223 4338 4441 4472 4553 4574 4591
4656 4662 4715 4745 4871 5021 5125 5223 5371 5489
5510 5648 5741 5821 6060 6235 6432 6708 6716 6868
6871 6876 6993 7070 7139 7162 7506 7535 7558 7769
7785 8016 8027 8134 8386 8584 8776 8905 8950 9034
9108 9134 9225 9393 9424 9591 9646 9792 9830 9847

ISSUED BY : THE DIRECTOR
NAGALAND STATE LOTTERIES, KOHIMA, NAGALAND
For Results, Please Visit : Www.Nagalandlotteries.Com
KINDLY CHECK THE RESULT WITH THE OFFICIAL GAZETTE

संपादकीय पृष्ठ

परीक्षा की घड़ी

पाकिस्तान में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक की सूचना के मुताबिक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश की आबादी का सातवां हिस्सा विस्थापित हो गया है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक कम से कम 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। संकट की इस स्थिति में स्वाभाविक ही दुनिया भर से मदद की पेशकश आने लगी है। लेकिन जिस तरह की आर्थिक चुनौतियों से पाकिस्तान पिछले कुछ समय से गुजर रहा है, उनके मद्देनजर इस आपदा से उपजी मुश्किलें इन सहायता सामग्रियों से हल होने वाली नहीं हैं। बेशक इनसे तात्कालिक मदद मिल जाएगी, जो अभी जरूरी भी है, लेकिन कठिनाइयां कई स्तरों पर आने वाली हैं। बाढ़ के चलते खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। इस लिहाज से कुछ समय बाद वहां खाने-पीने की वस्तुओं की किल्लत हो सकती है। बाढ़ के कारण बलूचिस्तान, सिंध और दक्षिण पंजाब से सब्जियों की सप्लाई बाधित हो गई है और इनकी कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के वित्त मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण है कि उनकी सरकार सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुएं भारत से आयात करने पर विचार कर सकती है। सर्वविदित है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अरसे से अच्छे नहीं चल रहे हैं। फिर भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ की इस विभीषिका को देखते हुए पाकिस्तान के लोगों के प्रति संवेदना जताई और उम्मीद जताई कि वहां जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे।

इतना ही नहीं, संकट काल में पाकिस्तान के लिए सहायता की घोषणा करने पर भी विचार चल रहा है। ध्यान रहे, दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आपसी व्यापार पर भी पड़ा है। फरवरी 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा समाप्त कर दिया था। उसने पाकिस्तान से होने वाले आयात को बैन तो नहीं किया लेकिन वहां से आने वाले माल पर शुल्क 200 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। इसके बाद अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म किए जाने पर पाकिस्तान की तत्कालीन इमरान खान सरकार ने भारत से हर तरह के व्यापार को स्थगित कर दिया था। हालांकि उसके बाद से धीरे-धीरे दवाओं और अन्य कई वस्तुओं के व्यापार की इजाजत मिली है, लेकिन फिर भी यह 2019 के सालाना 2.6 अरब डॉलर के स्तर से काफी नीचे है। ऐसे में दोनों देश चाहें तो बाढ़ के रूप में आई इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। सच है कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की प्रक्रिया बेहद जटिल है, लेकिन इस जटिलता को एक तरफ करके फिलहाल कम से कम व्यापार को धीरे-धीरे सामान्य रूप देने पर सहमति हो जाए तो वह भी एक उपलब्धि होगी।

चिंतित कराते आंकड़े : दिहाड़ी मजदूर कर रहे खुदकुशी

नवल किशोर कुमार

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) ने अपनी वार्षिक रपट सार्वजनिक कर दी है। अपराध के आंकड़े चिंतित करने वाले हैं।

दरअसल, भारत जैसे देश में जहां लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा है, वहां एक साल में 42 हजार 4 दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या निश्चित ही चिंता का सबब है। सनद रहे कि यह आंकड़ा वर्ष 2021 का है, जब पूरा देश कोरोना के खौफ में जी रहा था।

यह देश वह मंजर कभी नहीं भूलेगा जब प्रवासी मजदूर सड़क मार्ग से पैदल ही अपने गांवों में वापस लौट रहे थे। इसका प्रमाण तो इसी मंजर ने दे दिया था कि कोरोना के कारण पूरे देश में तालाबंदी का शिकार यदि कोई वर्ग होगा तो यही मजदूर वर्ग होगा। इसकी वजहें भी हैं। इन वजहों पर चर्चा आगे करते हैं। पहले तो एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की भयावहता के दूसरे आयामों को देखें ताकि समग्रता में बात की जा सके। एनसीआरबी की रपट कहती है कि वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2021 में खुदकुशी करने की घटनाओं में 7.17 फीसद की वृद्धि हुई है। यह संख्या एक लाख 53 हजार 52 है। इसमें 11.52 फीसद पेशेवर रहे। ये पेशेवर कौन थे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। ये पेशेवर भी मजदूर वर्ग के ही हैं, जिन्हें संगठित मजदूर की हैसियत हासिल है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अफरातफरी के माहौल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी व्यापक स्तर पर छंटनी की। इसके कारण लोगों में डिप्रेशन बढ़ा, कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हुए। कई तो असमय काल-कवलित हो गए। फिलहाल एनसीआरबी की रपट इसके प्रमाण देती है।

रही बात बेरोजगारों की तो वर्ष 2020 में 15 हजार 652 बेरोजगार युवाओं ने खुदकुशी की। हालांकि एनसीआरबी का दावा है कि बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है, और वर्ष 2021 में खुदकुशी करने वाले बेरोजगारों की संख्या 13 हजार 714 रही। इस आंकड़े में कमी की एक बड़ी वजह यह भी रही कि इस बार एनसीआरबी ने 9 श्रेणियां निर्धारित की थीं। इनमें विद्यार्थी, पेशेवर/वेतनभोगी, दिहाड़ी मजदूर, सेवानिवृत्त, बेरोजगार, स्वरोजगार, गृहिणी, किसान और अन्य शामिल रहे। खैर, आंकड़ों के परे स्थिति की भयावहता को समझने का प्रयास करते हैं।

चूंकि ये आंकड़े कोरोना काल के हैं, इसलिए यह तो मानना ही पड़ेगा कि कोरोना महामारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है, और इसका असर उस वर्ग पर सबसे अधिक पड़ा है, जो वंचित रहा है। इनमें दिहाड़ी मजदूरों की स्थिति दूसरी है। यह भी उल्लेखनीय है कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना महामारी के कारण भी मारे गए। इनमें भी उनकी संख्या अधिक रही जो प्रवासी मजदूर थे। चूंकि केंद्र सरकार ने पहले ही कह रखा है कि उसके पास मृतकों के बारे में सटीक आंकड़े नहीं हैं, तो यह तो साफ है कि बीमारी के कारण और खुदकुशी करने वाले मजदूरों की संख्या एनसीआरबी के आंकड़ों से अधिक ही होगी। असल में मजदूरों का वर्गीकरण दो तरह से करने का रिवाज है। एक संगठित क्षेत्र के मजदूर और दूसरा असंगठित क्षेत्र के मजदूर। संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए देश में श्रम कानून तय हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूर अनाथ मजदूर माने जाते हैं। इनके लिए श्रम कानून लगभग बेमानी होते हैं।

दिहाड़ी मजदूरों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर गौर किया जाना भी आवश्यक है। इनमें अधिकांश दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों के होते हैं। ये गांवों से शहरों में कमाने के लिए जाते हैं। इसकी वजह यह कि गांवों में अब पहले जैसे रोजगार के साधन नहीं रहे। इन वगरे में भूमिहीनता बड़ा सवाल रही है। ऐसे में इनके पास जीवन-यापन के लिए कोई और विकल्प नहीं होता। हालांकि देश में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भी है, जिसके तहत ग्रामीण मजदूरों को गांवों में ही कम-से-कम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है। यह भी व्यवस्था है कि कि यदि सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, तो मजदूरों को मुआवजा पाने का अधिकार है, लेकिन यह केवल कागजी बात है।

हकीकत यह है कि आज पूरे देश में मनरेगा योजना को विफल किया जा चुका है। आश्चर्यजनक तथ्य है कि वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत आवंटन में करीब 35 फीसद तक कमी की गई जबकि मनरेगा ने कोरोना महामारी के वक्त दिहाड़ी मजदूरों की आर्थिकी को मजबूती दी थी। खुदकुशी के आंकड़े सरकार पर सवाल उठाते हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस तरह के दावे कोरोना काल के दौरान केंद्र के स्तर पर किए गए या फिर राज्यों की सरकारों द्वारा किए गए, वे पूरे नहीं हो सके। मगर इससे भी बड़ा सवाल समाज की संवेदनशीलता का है। दरअसल, हुआ यह कि कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपना निजी काम भी ठप कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने मजदूरों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया। इस तरह की असंवेदनशीलता व्यापक स्तर पर पूरे देश में देखने को मिली। बहरहाल, खुदकुशी के मसले पर आंकड़ों से इतर जाकर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि श्रमिकों का वह वर्ग जो हर तरह से उपेक्षित है, उसके लिए ठोस उपाय किए जाएं। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि देश में खेती पर निर्भरता तेजी से घटती जा रही है (मानसून की अनिश्चितता ने आशंका को गहरा किया है) और लोग विनिर्माण व सेवा क्षेत्र की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं।

सरकार को श्रमिकों के संबंध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए ताकि दिहाड़ी मजदूरों को जान देने की नौबत न आए। यह तभी संभव है जब केंद्र सरकार दिहाड़ी मजदूरों को मजदूर मानेगी और उनके लिए भी श्रमिक कानूनों को प्रभावी बनाएगी। उन्हें भी उसी तरह का संरक्षण मिले, जिस तरह का संरक्षण संगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्राप्त है। रही बात प्रक्रिया तय करने की तो देश में संसद है। संसद को तत्परता से इस मसले पर विचार करना चाहिए। आखिर, वह भी तो सत्ता का अभिन्न हिस्सा है।

गिरता रुपया

अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले भारतीय मुद्रा का निरंतर अवमूल्यन हमें कुछ चौंकाता है और सोचने पर भी मजबूर करता है। डॉलर का मूल्य भारतीय मुद्रा में 80.11 रुपये हो गया है। जाहिर है, यह रिकॉर्ड गिरावट है, जिसको रोकने की कोशिश के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही। जो अर्थव्यवस्थाएं मूलभूत रूप से मजबूत होती हैं, उनको हर हाल में फायदा होता है, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था या अमेरिकी डॉलर को तुलनात्मक रूप से हो रहा है। रुपये के मूल्य में गिरावट का असर सीधे आम लोगों पर नहीं पड़ता, मगर उद्योग जगत या विशेष रूप से डॉलर में आयात-निर्यात करने वालों पर भार बढ़ता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी दो प्रतिशत भी नहीं है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था छह प्रतिशत से ज्यादा की गति से बढ़ने लगी है। इसके अलावा, आगामी वर्ष में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढेगी, वहीं अमेरिकी रफ्तार में कमी आने की आशंका है, लेकिन डॉलर महंगा हो रहा है। इससे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर को भी समझा जा सकता है। डॉलर के मुकाबले यूरो और पाउंड में भी गिरावट है। हालांकि, चीनी मुद्रा कुछ फायदे में दिखती है। एक डॉलर का मूल्य चीनी मुद्रा में 6.92 युआन है। चीनी मुद्रा मजबूत है, क्योंकि चीन पर अमेरिकी निर्भरता ज्यादा है।

सवाल यह उठता है कि डॉलर का भाव इस बार क्यों बढ़ा है? दरअसल, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने वहां मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए कुछ और समय तक ऊंची ब्याज दरों को बनाए रखने के संकेत दिए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध नकदी या निवेश में कमी आएगी, पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसी का नतीजा है कि रुपया पिछले सत्र के करीब 79.87 की तुलना में 80.11 प्रति डॉलर हो गया है। अमेरिका में महंगाई 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि भारत में 6.7 प्रतिशत की दर से। जाहिर है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद आधारभूत रूप से सशक्त है और वहां से चलने वाला धन पूरी दुनिया पर असर डालता है। चूंकि लंबे समय तक अमेरिका में उच्च ब्याज दर रहने वाली है, इसलिए अमेरिका के निवेशक व्यापार को विस्तार देने में अभी हिचकेंगे। यही कारण है कि अनेक देशों के शेयर बाजारों में बिकवाली का दौर है। ध्यान देने की बात है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इस साल ब्याज दरों में चार बार बढ़ोतरी कर चुका है और अगले महीने फिर बैठक होनी है। अमेरिकी डॉलर इस वर्ष अब तक रुपये के मुकाबले सात प्रतिशत चढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत फायदे में हो और भारत बडे. नुकसान में। फिर भी भारत को अपनी मूलभूत मजबूती को बढ़ाना चाहिए, ताकि यहां से विदेशी निवेश का पलायन न हो। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत विकट समय है। कच्चे तेल के भाव में फिर बढ़त दिख रही है, तो इससे भारत में ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। अभी महंगाई को नियंत्रित करने और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट थामने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। आज महंगाई और रुपये के मूल्य में स्थिरता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत के विकास की रफ्तार तेज हो रही है।

चीनी, खेती और लाभ का हिस्सा

के. सी. त्यागी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने आगामी चीनी वर्ष 2022-23 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 305 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। यह मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले 15 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। आगामी एक अक्तूबर से चालू होने वाले पेराई सीजन से यह लागू होगा। इसके लिए चीनी की बेसिक रिकवरी 10.25 फीसदी निर्धारित की गई है। इसका सीधा अर्थ है कि एक क्विंटल में 10.25 फीसदी चीनी निकलती है, तो किसान को 305 रुपये मिलेंगे।

गौरतलब है कि कृषि लागत मूल्य आयोग ने एक क्विंटल गन्ने का मूल्य 162 रुपये आंका है और इसमें 88.3 फीसदी की बढ़ोतरी का दावा किया गया है, जबकि स्वामीनाथन आयोग की मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत यह बढ़ोतरी पांच फीसद से अधिक नहीं है। गन्ने के मूल्य की एफआरपी में यह बढ़ोतरी पिछले वर्षों के मुकाबले अधिक है, लेकिन किसान संगठनों ने इसे नाकाफी बताकर आंदोलन की धमकी दी है, तो चीनी मिल मालिकों की संस्था एस्मा ने वृद्धि को अधिक बताकर चीनी के दामों में बढ़ोतरी की मांग की है और घरेलू बाजार में चीनी को भाव बढ़ाकर बेचने की छूट भी मांगी है।

पिछले कई वर्षों से चीनी उद्योग को लाभप्रद बनाने के कई प्रयास हुए हैं। किसानों का लगभग सभी चीनी मिलों पर बकाया बना रहता है, लिहाजा सरकार ने मिलों को बड़ी राहत देते हुए कर्ज चुकाने की आसान राह तैयार की। चीनी विकास कोष के माध्यम से बकाया राशि भुगतान करने के लिए आसान ऋण पुनर्गठन योजना के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत 24 महीनों की मोहलत मिल मालिकों को दी जाएगी। 171 चीनी मिलों पर वित्तीय संस्थानों का लगभग 31 हजार करोड़ रुपये बकाया है।

एस्मा ने स्वयं माना है कि वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय मिलों ने 43 लाख टन निर्यात का अनुबंध किया है। 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वर्तमान चीनी वर्ष में भारतीय मिलों के पास निर्यात से मुनाफा कमाने के स्वर्ण अवसर है। विदेशी बाजारों में चीनी भेजने से स्थानीय भंडार पर दबाव कम होगा और घरेलू बाजार में भी चीनी के दाम सुधरेंगे। भारतीय चीनी की सर्वाधिक मांग इंडोनेशिया, दुबई, अफगानिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों में रहती है।

इधर सरकार द्वारा एथेनॉल की 20 फीसदी खपत पेट्रोलियम पदार्थों में किए जाने पर चीनी उद्योग बम-बम है। यह योजना आगामी वर्ष के प्रारंभ से ही शुरू होने के संकेत हैं। वर्तमान में चीनी उद्योग एथेनॉल के 10 फीसदी के उद्देश्य को प्राप्त कर चुका है। प्रधानमंत्री विश्व जैव ईंधन दिवस पर घोषणा कर चुके हैं। सरकार ने इसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान भी सुरक्षित कर दिया है। देश भर में 14 हजार करोड़ रुपये की लागत से बारह टू जी एथेनॉल संयंत्र लगेंगे, जिससे 3,000 करोड़ लीटर एथेनॉल का हर वर्ष उत्पादन संभव हो सकेगा।

गन्ने की फसल नकदी कहलाती है, यानी बेचते ही पैसा हाथ में आ जाएगा। 'शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1996', जिसे भार्गव फार्मूला कहा जाता है, के अनुसार गन्ना उत्पादक किसान जिस दिन गन्ना मिल के गेट पर पहुंचा देता है, उसके 14 दिन के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, इसके बाद लंबित भुगतान पर 15 फीसदी वार्षिक ब्याज लगाने का प्रावधान है। किसान नेता बीएम सिंह द्वारा इलाहाबाद कोर्ट में दाखिल एक याचिका पर लखनऊ हाई कोर्ट भुगतान की तारीख तय कर चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा है। यहां आकर किसान लाचार हो जाता है।

खेती को लाभकारी बनाए बगैर कोई विकल्प नहीं है। बजट सत्र में कृषिमंत्री ने स्वयं माना है कि किसान परिवार की मासिक आमदनी 6,426 रुपये मासिक है और मासिक खर्च 6,223 रुपये दर्ज किया गया है।

डीजल, बिजली, खाद, मजदूरी, कीटनाशक दवाइयों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से लागत मूल्य काफी बढ़ चुका है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय है लिहाजा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी होनी चाहिए। मूल्य निर्धारण समिति (सीएपी) का पुनर्गठन कर किसान पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों को उसमें शामिल करके नई शुरुआत की जा सकती है।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के मायने

नारायण कृष्णमूर्ति

अगस्त का आखिरी रविवार एक खास कारण से यादगार रहेगा, क्योंकि उसी दिन सुपरटेक द्वारा बनाए गए ट्विन टावरों को कुछ ही सेकेंडों में ध्वस्त कर दिया गया। इन टावरों के निर्माण में कानूनों के घोर उल्लंघन के बारे में वर्षों से काफी कुछ लिखा गया है। वर्ष 2005 में, नोएडा प्राधिकरण ने एमराल्ड कोर्ट के निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी दी, जिसमें 14 टावर शामिल हैं, प्रत्येक में भूतल और नौ मंजिल (जी + 9) हैं। जून 2006 में नियमों में संशोधन किया गया और नए नियमों के तहत, 2006 के बाद नए आवंटियों के लिए फ्लोर एरिया रेश्यो (एफआरए) 1.5 से बढ़ाकर 2 कर दिया गया था।

दिसंबर 2006 में प्राधिकरण ने एमराल्ड कोर्ट के लिए पहली संशोधित योजना को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप इमारतों में नौ से 11 मंजिल को मंजूरी मिल गई। सुपरटेक को भी दो अतिरिक्त इमारतों (टावर 15 एवं 16) और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए मंजूरी मिली। छह साल बाद, 2012 में नोएडा प्राधिकरण ने नई योजना की समीक्षा की, जिसमें जुड़वां टावरों की ऊंचाई 40 मंजिल तय की गई थी। दो साल बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहली बार भवन नियमों के उल्लंघन के लिए 2014 में इन टावरों के विध्वंस का आदेश दिया।

पिछले आठ वर्षों में इसके बिल्डर पुनर्विचार की उम्मीद में इन्हें गिराए जाने में देरी करने में कामयाब रहे। अंततः 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इन टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया, क्योंकि इनके निर्माण में न्यूनतम दूरी का ख्याल नहीं रखा गया था। अदालत के अनुसार, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम के तहत व्यक्तिगत फ्लैट मालिकों की जरूरी सहमति के बिना इमारतों को अवैध रूप से बनाया गया था। मुख्य मुद्दा दो टावरों के बीच की दूरी भी थी, जो दो टावरों के बीच आवश्यक न्यूनतम 16 मीटर की दूरी से कम थी।

नियमों के उल्लंघन के लिए बिल्डर को दोष देना आसान है। हालांकि सभी रियल एस्टेट से संबंधित मामलों की तरह एमराल्ड कोर्ट की कहानी आज जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक व्यापक है। शहरीकरण और शहरी क्षेत्रों में आवास की बढ़ती आवश्यकता के नाम पर बिल्डरों के हितों के अनुरूप बिल्डिंग बायलॉज और निर्माण नियमों को बदला, जोड़ा और संशोधित किया गया है। पूरा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र ऐसे मामलों से भरा पड़ा है, जहां भोले-भाले और यहां तक कि कई पढ़े-लिखे लोगों ने बिल्डरों और दलालों द्वारा बेचे गए फ्लैट लालच में खरीद लिए।

भारतीय रियल एस्टेट उद्योग में सड़ांध गहरी है। हालांकि सुपरटेक ने दो ध्वस्त इमारतों के तहत अनुमानत: कम से कम 1,000 करोड़ रुपये गंवाए हैं, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है, जिससे कुछ भी बदलाव आएगा। कई अन्य बिल्डरों के विपरीत, जो प्रोजेक्ट की घोषणा के बाद गायब हो गए और यहां तक कि अधूरे भवन निर्माण के बाद खरीदारों को अधर में छोड़ दिया या कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिम्मेदार लोग अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। चालीस मंजिला इमारत रातोंरात नहीं बन गई, इन जुड़वां टावरों को बनाने में सुपरटेक को पांच वर्ष लगे।

प्रोजेक्ट के 14 अन्य टावरों के निवासियों, अधिकारियों और यहां तक जिम्मेदार नागरिकों को भी निर्माण की जानकारी थी। मामले को अदालतों में ले जाने से पहले रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुपरटेक से परियोजना को बंद करवाने का प्रयास किया। शर्मनाक बात यह है कि जिस न्यूनतम दूरी के उल्लंघन के लिए टावरों को ध्वस्त किया गया, उसका पालन अब भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर दो टावरों के बीच कुछ और ज्यादा दूरी होती, तो उन्हें ध्वस्त नहीं किया जाता।

कोई भी बिल्डर प्राधिकरण की मिलीभगत के बिना ऐसा नहीं कर सकता, जो परियोजना की गुणवत्ता और प्रगति की निगरानी के लिए जवाबदेह है। इसलिए यह आरोप गलत नहीं है कि नोएडा प्राधिकरण के जिन लोगों की निगरानी में यह पूरा ढांचा खड़ा हुआ था, वे भी किसी न किसी तरह इसमें शामिल थे।

आम आदमी के हित में काम करने वाली संस्थाओं के कामकाज को प्रभावी बनाने के क्या उपाय हैं? अधिकारियों की निष्क्रियता और खराब कार्यप्रणाली को रोकने का एक तरीका उनके कार्यों में जवाबदेही लाना है।

बिल्डर द्वारा भवन कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए उन्हें जवाबदेह होना चाहिए और ऐसा करने में कोई भी विफलता उनके काम न करने के बराबर है। प्रशासन और सरकार की भूमिका कानून को बनाए रखने और लोगों के हितों की रक्षा में विफलता का संकेत देती है। कानून के उल्लंघन के इस मामले को नोएडा प्राधिकरण ने नहीं उठाया था, बल्कि इसे शेष 14 टावरों के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अदालत में लेकर गया था। अदालतों में दृढ़ता से उनके खड़े रहने के कारण टावरों का विध्वंस हुआ।

यदि प्रशासन ने अपना काम किया होता, तो उन्हें विरोध प्रदर्शन करने और अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित इन जुड़वां इमारतों के विध्वंस ने एक सख्त संदेश दिया है, लेकिन इसमें काफी देर लगी। भारत जैसे देश में हम कचरों का जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन इन टावरों के विध्वंस ने कचरों में इजाफा किया है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन 80,000 टन मलबे के निष्पादन की है, जो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इन दोनों टावरों के विध्वंस से पहले कई साल मुकदमेबाजी में बीत गए, इस दौरान सरकार इन दोनों ढांचों से ज्यादा से ज्यादा सामग्री को सुरक्षित रूप से पुनर्प्राप्ति के तरीकों पर काम कर सकती थी और संभव होता, तो इसका इस्तेमाल कर सकती थी।

अब चर्चा इस बात की हो रही है कि कैसे ध्वस्त इमारतों के मलबे को कचरा प्रबंधन स्थल तक पहुंचाया जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए।

तथ्य यह है कि प्राधिकरण को मलबे को साफ करने के लिए बहुत से सफाईकर्मियों को लगाना पड़ा, जो दर्शाता है कि अब चर्चा भवन कानूनों के उल्लंघन के बारे में नहीं हो रही है, बल्कि इमारतों को ध्वस्त करने और आसपास के क्षेत्रों में सफाई की लागत के बारे में हो रही है। घर खरीदारों के लिए सबक यह है कि उसी घर के लिए भुगतान करें, जो रहने के लिए तैयार है और संबंधित अधिकारियों से जिसे सभी आवश्यक मंजूरी मिल गई है।

'सन सिटी' जोधपुर

थार के प्रवेश द्वार राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाद सर्वाधिक चहल-पहल वाला शहर है जोधपुर। यह शहर जयपुर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान शहर है। अपनी अनूठी विशेषता के कारण इस शहर को दो उपनाम-'सन सिटी' और 'ब्लू सिटी' मिले हैं। 'सन सिटी' नाम जोधपुर के चमकीले धूप के मौसम के कारण दिया गया है, जबकि 'ब्लू सिटी' का नाम मेहरानगढ़ किले के आसपास स्थित नीले रंग के घरों के कारण दिया गया है। जोधपुर को 'थार के प्रवेश द्वार' के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह शहर थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। जोधपुर शहर को 1459 में राजपूतों के राठौड़ राव जोधा ने स्थापित किया था। इससे पहले इस शहर को 'मारवाड़' नाम से जाना जाता था, किन्तु वर्तमान नाम शहर के संस्थापक राव जोधा के नाम पर है। इस किलेनुमा शहर को पत्थर की एक ऊंची दीवार संरक्षण प्रदान करती है। यह दीवार करीब 10 किलोमीटर लंबी है तथा विभिन्न दिशाओं में इसके 8 प्रवेश द्वार हैं। विशाल किले के अलावा अपने जमाने के खूबसूरत महलों, मंदिरों तथा उत्कृष्ट सं ग्रहालयों के कारण यह शहर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो आइए, क्यों न चलें उन स्थलों की ओर-

जसवंत थांडा : मेहरानगढ़ किले के नजदीक सफेद संगमरमर की बनी महाराजा जसवंत सिंह की समाधि दर्शनीय है। इसका निर्माण 1899 में किया गया था। यहां के विभिन्न चित्रों और समाधियों में उस युग की शाही वंशावली सुरक्षित है। 4 समाधियां संगमरमर की बनी हैं।

मेहरानगढ़ किला : यह भव्य किला 120 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। सामरिक कारणों से 1459 में राव जोधा ने अपनी राजधानी मंडौर से यहां बदल ली थी। इस खूबसूरत किले के अंदर मोती महल, फूल महल और शीश महल आदि मौजूद हैं। ये सभी भवन शिल्पकला व भवननिर्माण कला के अद्भुत नमूने हैं। शाही परिवार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाली मेहराबदार खिड़कियां, आगे खूबसूरत डिजाइन में निकले छज्जे, बलुई पत्थर पर की गयी सुंदर व बारीक नक्काशी, पत्थर के खुदे हुए लुक आदि काबिलेतारीफ है। इस किले को देखकर मन रोमांचित हो जाता हैं। घूमते समय यहां की अद्भुत कलाएं मोहित कर लेती हैं।

उमैद भवन : इस उत्कृष्ट भवन का निर्माण महाराजा उमैद सिंह ने 1829-42 में करवाया था। उस समय इस खर्चीले भवन के निर्माण में 15 लाख रुपये खर्च हुए थे। यह अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए महाराजा उमैद सिंह द्वारा किया गया एक सार्थक उपाय था। इसके 347 कमरों को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से संवारा गया था। वर्तमान समय में महल का एक भाग कुछ भूतपूर्व शासकों का निवास स्थान है। वाकी भाग को एक बड़े होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। महल के अंदर खूबसूरत जोधपुर उमैद भवन बाग भी है। महल के कुछ भाग ही पर्यटकों के लिए खुले हैं।

कालियाना झील : यह शहर से 11 किलोमीटर दूर जैसलमेर मार्ग पर कृत्रिम झील के किनारे का क्षेत्र एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है। पर्यटक यहां से खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद जरूर लेते हैं। यहां का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है, जैसे आसमान के कैनवास पर किसी ने अनगिनत रोमांटिक रंग छिड़क दिए हों। यहां का खूबसूरत दिलकश नजारे को पर्यटक दिलों में बसा लेते हैं।

बलसमंद लेक व पैलेस : शहर से 7 किलोमीटर दूर यह एक मनोहारी पर्य टक स्थल है। जहां आम, अमरूद, पपीते के अलावा अन्य घने वृक्षों की खूबसूरती तो देखते बनती ही है, साथ में इन वृक्षों से आती ठंडी हवाएं पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। यहां की कृत्रिम झील के किनारे शांत वातावरण में पर्यटक अद्भुत शांति महसूस करते हैं। इस झील का निर्माण 1159 में बालक राव परिहार ने किया था।

जोधपुर में कई मंदिर दर्शनीय हैं - महामंदिर मंदिर, रसिक बिहारी मंदिर, गणोश मंदिर, बाबा रामदेव मंदिर, संतोषी माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर और अचलनाथ शिवालय लोकप्रिय मंदिरों में हैं।

मंडौर बाग : शहर से 9 किलोमीटर दूर स्थित मंडौर मरवाड़ की पुरानी राजधानी रही है, जिसे सामरिक कारणों से बदलना पड़ा। आज भी इसके भग्नावशेष मौजूद हैं। अब यह खूबसूरत घने बागों के बीच स्थित पिकनिक स्थल बन गया है। यहां भी पर्यटकों को भरपूर सुकून मिलता है और आनंद की अनुभूति होती है।

कब जाएं

इस क्षेत्र में वर्षभर गर्म और शुष्क जलवायु बनी रहती है। ग्रीष्मकाल, मानसून और सर्दियां यहां के प्रमुख मौसम हैं। इसलिए साल के किसी भी महीने में जोधपुर का कार्यक्रम बना सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है।

कैसे जाएं

जोधपुर शहर का अपना हवाई अड्डा और रे लवे स्टेशन है। प्रमुख शहरों से उड़ानें और रेल सुविधाएं हैं। सड़क मार्ग से भी प्राय- सभी बड़े शहरों से पंहुच सकते हैं।

गंगा के किनारे बसी बाबा विश्वनाथ की काशी

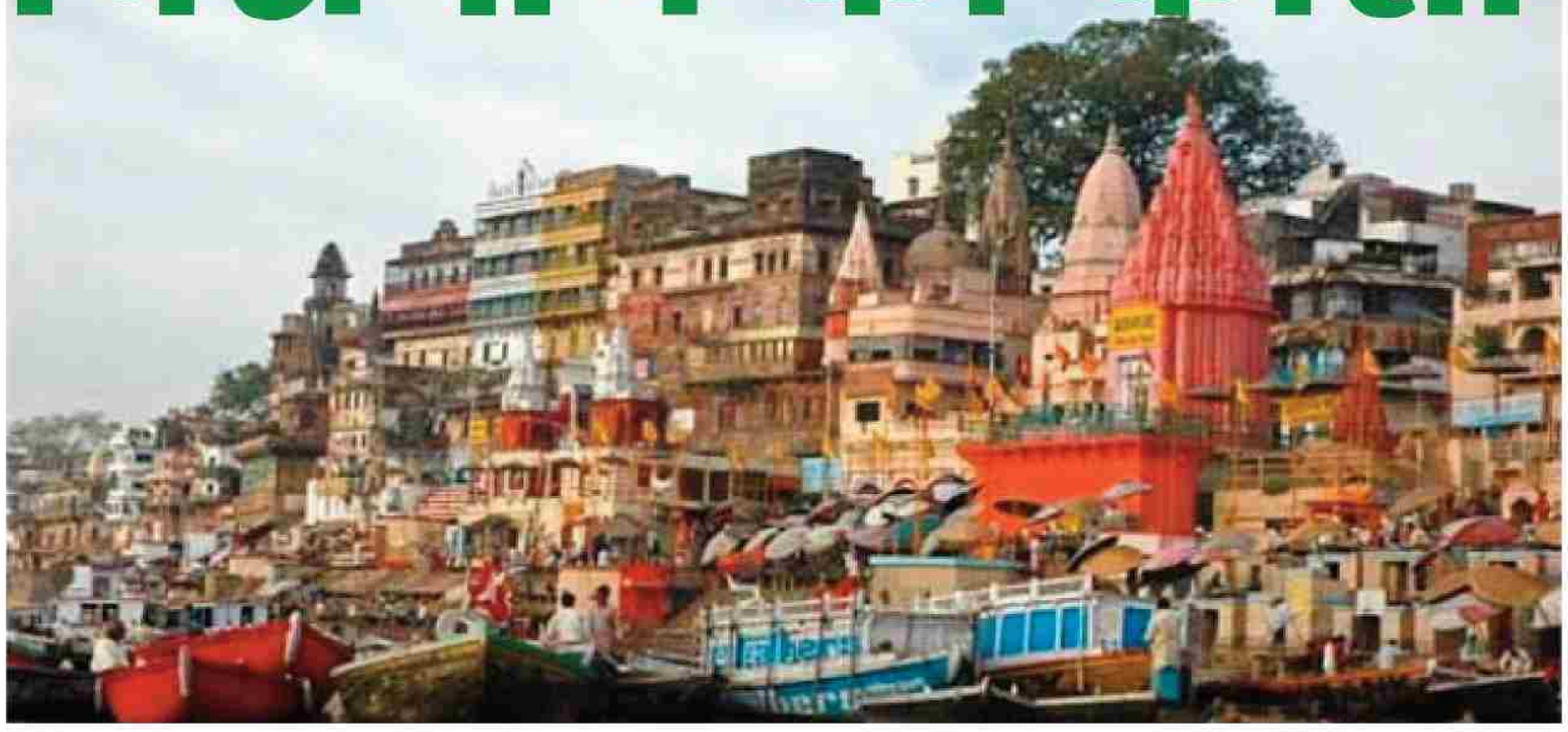

लोक, कला और पर्यटन के मामले में वाराणसी बेहद समृद्ध है। यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। यहां गंगा के घाट सदियों पुराना इतिहास समेटे हुए हैं। भगवान शिव का प्रसिद्ध तीर्थस्थल होने के कारण भी यहां साल भर पर्यटक खिंचे चले आते हैं। यह शिव की काशी नगरी है। साक्षात् विराजमान हैं महादेव यहां। वाराणसी की यात्रा एक तरह से शिव से मुलाकात है। मन का मैल धोना हो, मन का बोझ उतारना हो था फिर चाहिए मुक्ति तो एक बार काशी चले आइए और गंगा तट पर स्नान कर महादेव से साक्षात्कार कीजिए।

ये काशी ही है जो पूरी दुनिया को बुलाती है- आओ मुझसे मिलो। यहां के घाट, मैरी चर्च, भारत कला म्यूजियम, राम नगर दुर्ग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय व नंदेश्वर कोढी दर्शनीय हैं। इन सबके अलावा यहां का काशी विश्वनाथ मंदिर विश्वविख्यात है। इसके अलावा तुलसी मनस मंदिर, भारत माता मंदिर और दुर्गा मंदिर बेहतरीन मंदिरों में से एक है।

वाराणसी के आसपास भी पर्यटक स्थल हैं, जहां आप भ्रमण कर सकते हैं जैसे चुनार, सारनाथ और जौनपुर। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुयरी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुयरी एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट हैं। वाराणसी में साल भर मेले और त्योहार पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इनमें से कुछ त्योहार प्रमुख माने जाते हैं जैसे कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, गंगा महोत्सव, रामलीला, हनुमान जयंती, पंच कोशी परिक्रमा और महाशिवरात्रि।

वाराणसी के मंदिर श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण माने जाते हैं। यहां के मंदिर देखने दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। बनारस के ज्यादातर मंदिर पुराने शहर के रास्ते में हैं। सबसे मुख्य मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर हैं, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। पूरे साल यहां भगवान शिव के भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में शाम की आरती बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसे देखने श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं।

बनारस शहर की पवित्रता यहां की बहती नदी गंगा के साथ भी जुड़ी है। बनारस स्थित गंगा घाट पर पर्यटकों और वहां के स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रहती हैं। दशमेघ घाट, अस्सी घाट, बहना संगम, पंचगंगा और मणि कर्णिका, यहां के मुख्य घाटों में से हैं। इन घाटों के पीछे कई किवदंतियां हैं। सुबह इन घाटों पर लोगों की भीड़ रहती है, जो गंगा नदी में डुबकी लगाकर उगते सूरज की आराधना करते हैं।

वाराणसी से नजदीक हैं सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था प्रबोधन पाने के बाद। सम्राट अशोक ने बाद में यहां स्तूप भी बनवाया था। सारनाथ में कई सारे बौध स्मारक बने। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार यहां उत्साहपूर्वक मनाया जाता है।

वाराणसी आप कभी भी जा सकते हैं। दिल्ली से सीधी ट्रेन वाराणसी जाती है। कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से पर्यटक काशी पहुंच सकते हैं। यहां कभी भी घूमने जाया जा सकता है। मगर फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय अच्छा रहता है।

घूमने बिहार जाएँ तो इन दस ठिकानों को न भूल जाएँ!

पर्यटन के हिसाब से बिहार समृद्ध है। यहां देखने के लिए बहुत कुछ हैं। बिहार के नाम विहारा से बनाया गया। मतलब भ्रमण करने की जगह। विश्व का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने का गौरव बिहार को ही हासिल है। विभिन्न धर्मों के स्मारक भी यही देखने को मिलते हैं। बिहार में ऐसी दस मुख्य जगह हैं, जहां आप घूम सकते हैं।

नालंदा विश्वविद्यालय- पांचवीं शताब्दी में बना यह विश्वविद्यालय विश्व का पहला रेसिडेंसियल यूनिवर्सिटी है। यहां ज्ञान की रोशनी सभी को अलोकित करती है। किसी समय लगभग 2000 शिक्षक देश-विदेश से आए दस हजार छात्रों को पढ़ाते थे। यहां बुद्ध ने भी एक शिक्षक की भूमिका निभाई। महान विद्वान और चीनी पर्यटक ह्यून सेंग भी यहां के छात्र रहे थे। यह विश्वविद्यालय कुशान वास्तुकला का बेहतरीन नमूना हैं। बरसों बंद रहने के बाद आज यह विश्वविद्यालय आंशिक रूप से फिर से शुरू हो गया है।

बोधि वृक्ष- पटना से सौ किलोमीटर दूर गया में बोधि वृक्ष बौद्धों का महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं। पूरे विश्व से बौद्ध समुदाय के लोग इस वृक्ष के सामने नतमस्तक होते हैं। कहते हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। वृक्ष के पास ही महा बोधि मंदिर है, जो बौद्ध धर्म अपनाने वालों के लिए पवित्र स्थल हैं।

मचालिंडा झील- मचालिंडा झील के शेषनाग के नाम पर पड़ा है। दरअसल, सांपों के राजा मचालिंडा ने भगवान बुद्ध को इसी झील के पास उनके छठे हफ्ते के ध्यान के समय भयंकर आंधी और लहरों से बचाया था। इस वजह से यह जगह मचालिंडा के नाम से जाना जाता हैं। बोध गया में इस जगह के आस-पास की हरियाली इसे बेहतरीन पर्यटक स्थल बनाती हैं।

गिद्धहकुटा पीक- यह पीक वल्चर पीक के नाम से जाना जाता हैं। राजगीर स्थित यह पीक बिल्कुल एक गिद्ध की तरह हैं। महात्मा बुद्ध ने इस पीक पर अपने कुछ प्रसिद्ध उपदेश दिए थे और तब से यह बौधों के लिए पवित्र स्थल बन गया।

राजगीर का गर्म कुंड- राजगीर का हॉट स्प्रिंग्स पर्यटकों के लिए खास जगह हैं। वैभव पहाड़ियों के नीचे इस गर्म कुंड में नहाने के लिए दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। इस कुंड में पानी सप्तधारा से आता हैं। यह धारा सप्तपर्णी गुफा के पीछे से बहती हैं। कहते हैं यह कुंड अपने आप में औषधीय गुण समेटे हुए है। ब्रहमकुंड यहां का सबसे गर्म कुंड माना जाता है। इसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता हैं। कहा जाता है भगवान बुद्ध और महावीर ने भी इस कुंड में स्नान किया था।

बक्सर फोर्ट- गंगा नदी के तट के साथ बसे बक्सर के प्राचीन किले को 1054 में बनाया गया था। इस किले की बनावट बेहद उत्कृष्ट हैं। यह किला अंदर से भी बेहद आकर्षक हैं। अगर आप बक्सर जाएं तो इस किले का भ्रमण करना न भूलें। साथ ही यहां का गौरी शंकर मंदिर और नाथ बाबा मंदिर भी दर्शनीय है।

नवलखा पैलेस- मधुबनी जिले के राजनगर में इस पैलेस का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। 1934 में आए भूकम्प के कारण इस पैलेस को काफी क्षति पहुंची थी। उसके बाद इसका निर्माण नहीं हो पाया। इसके अलावा कमला नदी के पास मां काली मंदिर और मां दुर्गा को समर्पित राजनगर पैलेस यहां का मुख्य पर्यटक स्थल हैं।

हेन सैंग मेमोरियल हॉल- प्रसिद्ध चीनी विद्वान ह्यून सेंग की याद में बनाया गया यह हॉल अद्भुत शिल्पकला का उदाहरण हैं। कहते हैं उन्होंने भारत में अपने बारह साल यहीं गुजारे थे। आचार्य शील भ्रद की छत्रछाया में उन्होंने यहां योग सीखा।

जलमंदिर- झील के बीचोंबीच कमल के फूल से घिरा है। यह जलमंदिर। ऐसा कहा जाता है। भगवान महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने इसे बनाया था। यह मंदिर विमान के आकार में है। 600 फीट लंबा पुल इस मंदिर को किनारे से जोड़ता हैं। इसी जगह भगवान महावीर ने महाप्रयाण किया था।

पटना म्यूजिक- 1917 में बना म्यूजिक पर्यटकों के लिए खास आकर्षण केंद्र हैं। राजपूत और मुगल वास्तुकला से समृद्ध इस म्यूजियम में पेटिंग्स, पौराणिक चीजें और अन्य प्रतिरूप रखे जाए हैं। यहां हिंदू और बौध धर्म की वस्तुओं का विशेष संग्रह हैं। 20 करोड़ साल पुराने पेड़ का अवशेष भी यहां रखा हैं।

संस्कृति के हिसाब से बिहार में देखने के लिए बहुत कुछ हैं। इन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आप भी रेलमार्ग या वायुमार्ग से यहां आ सकते हैं।

पाकिस्तान में बाढ़ से बुरा हाल, 20 लाख एकड़ में फैली फसल बर्बाद

इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस समय बाढ़ के कहर से जूझ रहा है और यहां केवल 10 दिनों के अंदर इतनी भारी बारिश हुई है कि इसने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। बारिस के कारण पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा डूब गया है। अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए है।

बाढ़ से आई इस तबाही से अब तक 7 लाख से ज्यादा पशु मारे गए हैं और 3 हजार किलोमीटर की सड़कें पानी से बह गई है जिसके कारण लोगों तक राहस सामाग्री पहुंचने में काफी दिक्कते आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि बाढ़ का असर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, खैबर-पख्तूनख्वा और पंजाब राज्य में देखने को मिला है। यहां लगभग 20 लाख एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ के कारण पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है।

अचानक कैसे आई बाढ़

पाकिस्तान में बाढ़ के आने का कारण यहां का जलवायु परिवर्तन है। दुनियाभर में बढ़ते तापमान को लेकर यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पृथ्वी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। तापमान बढ़ने और समुद्र के पास होने से गर्म हवाएं हिमालय से टकराती है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश होती है। पाकिस्तान में इस बार 385 मिमी बारिश हुई है और विशेषज्ञों के मुताबिक यहां बारिश सितंबर तक होने की संभावना है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस अगले सप्ताह पाकिस्तान की यात्रा पर जाएंगे। इस बाढ़ से लाखों लोगों की स्थिति को देखने के लिए गुटेरेस पाकिस्तान पहुंचेंगे।

बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान को तीन करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देगा अमेरिका

वाशिंगटन। अमेरिका ने बाढ़ ग्रस्त पाकिस्तान को तीन करोड़ डॉलर की मानवीय सहायता देने की मंगलवार को घोषणा की। अमेरिका के विदेश एंथनी ब्लिंकन ने कहा, '' हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।'' उन्होंने कहा, '' पाकिस्तान के भयानक बाढ़ की चपेट में आने के कारण अमेरिका 'यूएसएआईडी' के जरिए भोजन, सुरक्षित पेयजल और आश्रय जैसी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए तीन करोड़ डॉलर प्रदान कर रहा है।'' विदेश मंत्रालय के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने पत्रकारों को बताया कि बाढ़ से अनुमानित 3.3 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और 1,100 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि 1,600 से अधिक लोग घायल हैं। पटेल ने बताया कि 'यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' (यूएसएआईडी) के साझेदार इस कोष का इस्तेमाल भोजन, पोषण, सुरक्षित पेयजल, बेहतर स्वच्छता, आश्रय सहायता आदि जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए करेंगे। पाकिस्तान हाल के इतिहास में सर्वाधिक भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है।

सोलोमन द्वीप ने मंजूरी प्रक्रिया की समीक्षा होने तक सैन्य पोत नहीं भेजने का अनुरोध किया

कैनबरा । सोलोमन द्वीप ने आग्रह किया कि जब तक मंजूरी की प्रक्रिया की समीक्षा नही कर ली जाती तब तक देश अपने नौसनिक पोत नहीं भेज। इस अनुरोध से पहले अमेरिकी तटरक्षक पोत ओलिवर हेनरी और ब्रिटिश नौसैनिक गश्ती नौका एचएमएस स्पे की यात्रा गत सप्ताह रद्द कर दी गई थी। सोलोमन और चीन के बीच हुए नए सुरक्षा समझौते के बीच अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि समझौते के कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से दो हजार किलोमीटर से कम दूरी पर एक चीनी नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा सकता है। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री मानासेह सोगवारे ने कहा है कि ओलिवर हेनरी ने समय पर सूचना नहीं दी थी, इसकारण उनके कार्यालय ने यात्रा को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि एचएमएस स्पे ने दौरे का आवेदन वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, मंजूरी मिलने में देरी से पता चलता है कि सैन्य पोतों को सोलोमन द्वीप के दौरे के लिए अनुमति देने के वास्ते सरकार को आवश्यकताओं की समीक्षा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमने अपने साझेदारों से अनुरोध किया है कि वे नई प्रक्रिया की समीक्षा के लिए समय दें और उसके बाद सैन्य पोतों के दौरों के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि नयी प्रक्रिया सभी सैन्य पोतों के लिए लागू होगी।

तुर्की और ईरानी अधिकारियों ने मारे 14 अफगान शरणार्थी

काबुल । एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तुर्की और ईरानी सीमा अधिकारियों पर पिछले साल कम से कम 14 अफगान शरणार्थियों की हत्या करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में ईरानी सुरक्षा बलों द्वारा 11 अफगानों और तुर्की सुरक्षा बलों द्वारा 3 की 'गैरकानूनी हत्या' का दस्तावेजीकरण किया था।

राइट्स ग्रुप ने कहा कि ईरानी और तुर्की सुरक्षा बलों ने देशों को पार कर रहे अफगानों पर हमला किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी सुरक्षा बलों ने भीड़-भाड़ वाली कारों पर बार-बार गोलियां चलाईं, जबकि तुर्की के सीमा प्रहरियों ने अवैध रूप से गोला-बारूद का इस्तेमाल किया।

बता दें कि अगस्त 2021 में अफगान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से ये आंकड़े उस अवधि से संबंधित हैं। तब से देश में मानवीय स्थिति काफी खराब हो गई है। तुर्की यूरोपीय देशों के नागरिकों को कन्वेंशन के तहत शरणार्थी का दर्जा देता है, जबकि सीरियाई शरणार्थियों को केवल एक अस्थायी सुरक्षा का दर्जा प्रदान करता है। अन्य गैर सरकारी संगठनों की कई रिपोर्टों से पता चलता है कि अधिकांश भाग के लिए तुर्की में अफगानों को शरणार्थी का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। तुर्की के गृह मंत्रालय के अनुसार, इस साल अब तक लगभग 43,000 अफगानों को अफगानिस्तान भेजा जा चुका है।

नहीं रहे सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, 91 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

मॉस्क। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। रूसी समाचार एजेंसी 'तास', 'आरआईए नोवोस्ती' और 'इंटरफैक्स' ने 'सेंट्रल क्लीनिकल हॉस्पिटल' के हवाले से गोर्बाचेव के निधन की जानकारी दी। गोर्बाचेव के कार्यालय ने पहले बताया था कि अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है।

ऋषि सुनक खेमा ने प्रतिद्वंद्वी लिज ट्रस पर जांच से बचने का आरोप लगाया

लंदन,। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन के स्थान पर नए नेता की नियुक्ति के लिए शुक्रवार को मतदान पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी होने के बीच पूर्व मंत्री ऋषि सुनक के खेमे ने मंगलवार को प्रतिद्वंद्वी लिज़ ट्रस पर जांच से बचने का आरोप लगाया। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों और सट्टेबाजों के अनुमानों के अनुसार विदेश मंत्री ट्रस मौजूदा होड़ में सबसे आगे हैं। उन्हें बीबीसी के अनुभवी राजनीतिक पत्रकार निक रॉबिन्सन के कठिन सवालों का जवाब देना था। लेकिन कैबिनेट मंत्री ने साक्षात्कार के मंगलवार शाम को प्रसारित होने से कुछ घंटे पहले इससे इनकार कर दिया। उनकी टीम से कहा कि अब उनके पास समय नहीं हैं। सुनक इस महीने की शुरुआत में ही निक रॉबिन्सन के सवालों का जवाब दे चुके हैं। बीबीसी ने एक बयान में कहा कि लिज़ ट्रस ने निक रॉबिन्सन के साथ अपना साक्षात्कार रद्द कर दिया है जो इस मंगलवार शाम (30 अगस्त) शाम सात बजे प्रसारित होने वाला था ऋषि सुनक के एक सहयोगी ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों को उचित जांच का सामना करना पड़े ताकि [पार्टी] सदस्य और आम जनता को पता चल सके कि वे क्या पेशकश कर रहे हैं। सहयोगी ने दावा किया कि इस जांच से बचने से पता चलता है कि ट्रस के पास कोई योजना नहीं है।

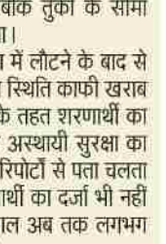

तुर्की में लोग एक एयरोस्पेस व टेक्नोलॉजी मेले में पहले मानवरहित लड़ाकू विमान के प्रतिरुप को देखते हुए।

ताइवान की राष्ट्रपति ने चीनी खतरे के बीच सैनिकों को संयमित रहने को कहा

पेंघु (ताइवान)। ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने मंगलवार को स्वशासित द्वीप की सैन्य इकाई से कहा कि वे चीन द्वारा दैनिक आधार पर भेजे जा रहे विमान और युद्धपोतों को लेकर सर्यमित रहें। उन्होंने कहा कि ताइवान, चीन को संघर्ष भड़काने का मौका नहीं देगा। उल्लेखनीय है कि अगस्त महीने के शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइपे यात्रा के बाद से ताइवान पर सैन्य दबाव बनाए हुए है। चीन ने शुरुआत में इस यात्रा के जवाब में ताइवान के नजदीक समुद्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया था और फिर ताइवान के ऊपर से मिसाइल दागी थीजो जापान के आर्थिक क्षेत्र में गिरी थी। राष्ट्रपति वेन चीन द्वारा प्रतिदिन डाले जा रहे दबाव के बावजूद सर्यमित हैं। उन्होंने ताइवान के पश्चिमी तट पर पेंघु स्थित नौसेना के ठिकाने के दौरा किया और सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, '' दुश्मन जितना भी उकसावे की मुद्रा में हो, हमें उतना ही संयमित रहने की जरूरत है। हमें उन्हें संघर्ष करने के लिए बहाना नहीं देंगे।'' इस दौरान उन्होंने रडार स्क्वाड्रन, वायु रक्षा कंपनी का निरीक्षण किया।

इंडोनेशिया के बाली में जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक, विकासशील देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा

नुसा दुआ (इंडोनेशिया)। (एजेंसी)।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा के लिए इंडोनेशिया के बाली में जी20 मंत्रिस्तरीय बैठक हो रही है,जिसमें दुनिया के अग्रणी अमीर और विकासशील देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक से पहले इंडोनेशिया की पर्यावरण मंत्री सीति नूरबाया ने कहा कि बैठकों के दौरान, जी-20 समूह के हर सदस्य देश के योगदान और विकसित तथा विकासशील देशों के लक्ष्यों में तालमेल बिठाने पर चर्चा की जाएगी।

नूरबाया ने उम्मीद जताई कि पेरिस में हुए जलवायु समझौते को साकार करने के लिए बैठक में प्राथमिकता वाले तीन बिंदुओं- पर्यावरण को हुए नुकसान से उबरने की सतत प्रक्रिया, जलवायु पर भूमि आधारित और समुद्र आधारित कार्रवाई तथा संसाधनों के समुचित उपयोग पर संयुक्त समझौता हो सकता है। मंत्री ने बैठक का उद्घाटन करते हुए अन्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह किया कि पर्यावरणीय बहुपक्षवाद की रक्षा की जाए और उसे अमल में लाया जाए क्योंकि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से समन्वित प्रयास करने का यही एकमात्र तरीका है।

नूरबाया ने कहा, ÷पर्यावरणीय बहुपक्षवाद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जहां छोटे, बड़े, अमीर या गरीब देश सभी समान ऊंचाई वाले मंच पर खड़े हो सकते हैं। चाहे उत्तर में हों या दक्षिण, विकसित या विकासशील, सभी देशों की आवाज सुनी जानी चाहिए।÷ इस साल जी-20 समूह की अध्यक्षता इंडोनेशिया कर रहा है जिसने पेरिस समझौते 2016 का समर्थन किया है। इंडोनेशिया ने 2030 तक अंतरराष्ट्रीय सहायता से 41 प्रतिशत और स्वतंत्र रूप से 29 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिका के जलवायु प्रतिनिधि जॉन केरी समेत 17 पर्यावरण मंत्री और 200 से ज्यादा अन्य प्रतिनिधि इस बैठक में भाग ले रहे हैं। चीन, रूस और अर्जेंटीना के प्रतिनिधि डिजिटल माध्यम से इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

किसी भी देश का रूस के साथ सैन्य अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है: व्हाइट हाउस

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ अकारण एवं बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने रूस में एक से सात सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास 'वोस्तोक 2022' के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। इस सैन्य अभ्यास में भारत और चीन भी हिस्सा ले रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद से रूस में होने जा रहा यह पहला बड़े स्तर का अभ्यास है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने एयर फोर्स वन विमान पर पत्रकारों से कहा, ''किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ा है, लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं यह फैसला उन पर छोड़ती हूं।'' जब पियरे से यह पूछा गया कि क्यों ''भारत पर कोई दबाव नहीं है'', तो उन्होंने कहा ,''इस बारे में मेरा कहना यही है कि रूस ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना चिंताजनक है।'' पत्रकार ने प्रेस सचिव से प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की या वह किसी प्रकार की योजना बना रहा है, उन्होंने कहा ''मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ नहीं है।

अवमानना मामले में इमरान खान ने महिला न्यायाधीश के विरूद्ध अपनी टिप्पणी वापस लेने की इच्छा जतायी

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक महिला न्यायाधीश के विरूद्ध अपना विवादास्पद बयान वापस लेने की इच्छा जतायी लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। इसी माह के प्रारंभ में एक रैली में खान ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किये गये अपने सहयोगी शहजाब गिल के साथ किये गये बर्ताव को लेकर पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग एवं राजनीतिक विरोधियों के विरूद्ध मामला दर्ज कराने की धमकी थी। साथ ही उन्होंने अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी पर भी ऐतराज जताया जिन्होंने गिल को दो दिनों के लिए इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में भेजा था।

इस भाषण के बाद खान पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने खान के विरूद्ध अदालत की अवमानना कार्यवाही भी शुरू की। उच्च न्यायालय को अपने लिखित जवाब में खान ने दावा किया कि टिप्पणी करने के समय उन्हें पता नहीं था कि चौधरी न्यायिक अधिकारी हैं, उन्हें लगा था कि वह कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं। उन्होंने कहा , ''प्रतिवादी खान विनम्रता के साथ कहता है कि उनके द्वारा इस्तेमाल किये गये शब्द अनपयुक्त हैं और वह उसे वापस लेने को तैयार हैं।

अफगानिस्तान में 60 लाख लोग हो सकते हैं अकाल से प्रभावित: संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र (संरा) ने आगाह किया है कि बढ़ती गरीबी से जूझ रहे अफगानिस्तान के 60 लाख लोगों पर अकाल से प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। संरा के मानवीय सहायता प्रमुख ने सोमवार को दानदाताओं से अनुरोध किया कि वे आर्थिक विकास के लिए वित्त मुहैया करना फिर से शुरू करें और ठंड के मौसम में अफगानिस्तान की मदद के लिए तुरंत 77 करोड़ अमेरिकी डॉलर मुहैया करें। मार्टिन ग्रिफिथ्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि मानवीय, आर्थिक, जलवायु, भुखमरी और वित्तीय संकट जैसे कई संकटों का अफगानिस्तान सामना कर रहा है।

संघर्ष, गरीबी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और खाद्य असुरक्षा लंबे समय से अफगानिस्तान की एक दुखद वास्तविकता रही है। मार्टिन ने कहा कि जो चीज अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को 'इतना गंभीर' बनाती है, वह है एक साल पहले तालिबान द्वारा काबुल की सत्ता पर कब्जा किये जाने के बाद से बड़े पैमाने पर विकास सहायता को रोक दिया जाना। मार्टिन ने कहा कि आधी से अधिक अफगान आबादी (लगभग 2.4 करोड़ लोगों को) राहत सहायता की आवश्यकता है और करीब 1.9 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं।

मार्टिन ने कहा, ''हमें चिंता है कि हालात जल्द ही बदतर हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम पहले से ही काफी उच्च स्तर पर पहुंच चुकी ईंधन और खाद्य सामग्री की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और उनके गैर सरकारी संगठन साझेदारों ने पिछले एक साल में लगभग 2.3 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम की तैयारी के लिए 61.4 करोड़ डॉलर की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें आवास की मरम्मत-उन्नयन और गर्म कपड़े और कंबल प्रदान करने का खर्च शामिल है।

मार्टिन ने कहा कि ठंड के कारण कुछ क्षेत्रों से संपर्क कट जाने से पहले, वहां तक भोजन और अन्य आपूर्ति के लिए अतिरिक्त 15.4 करोड़ डॉलर की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तालिबान के पास अपने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के लिए कोई बजट नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि कुछ विकास सहायता शुरू करने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 70 प्रतिशत से अधिक अफगानों के लिए मार्टिन ने चेतावनी दी कि यदि कृषि और पशुधन की रक्षा नहीं की गई, तो लाखों लोगों का जीवन और आजीविका खतरे में पड़ जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे देश की खाद्य उत्पादन क्षमता खतरे में पड़ जाएगी। रूस ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई तथा उसके राजदूत वासिली नेबेंजिया ने अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के (अफगानस्तान में) '20 वर्षीय अभियान' के लिए तीखी आलोचना की।

राष्ट्रपति पद पर चिनफिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए अक्टूबर में मंजूरी देने की सीपीसी की योजना

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पांच साल का तीसरा कार्यकाल प्राप्त होने की संभावना है। यहां 16 अक्टूबर को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के एक अधिवेशन में उन्हें आजीवन इस पद पर बने रहने के लिए मंजूरी मिलने वाली है, हालांकि यह विशेषाधिकार अब तक सिर्फ पार्टी के संस्थापक माओत्से तुंग को ही मिला था। शी के अलावा, अधिवेशन में देशभर से 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक नयी आधिकारिक टीम को अपनी मंजूरी देंगे।

ज्यादातर शीर्ष पदाधिकारी या तो सेवानिवृत्त हो जाएंगे या हर पांच साल पर होने वाले पार्टी के अधिवेशन में नये पद प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री ली केकियांग पिछले 10 वर्षों से सत्ता में हैं। यहां की गई एक अधिकारिक घोषणा के मुताबिक, मंगलवार को सीपीसी के राजनीतिक ब्यूरो की एक बैठक की अध्यक्षता शी (69) ने की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पार्टी के पदाधिकारियों की भागीदारी वाला इसका एक पूर्ण सत्र नौ अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। उसमें यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि 20वां अधिवेशन बीजिंग में 16 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा।

चिनफिंग की अध्यक्षता में हुई राजनीतिक ब्यूरो की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सीपीसी का 20वां अधिवेशन इस नाजुक घड़ी में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी पार्टी और समूचा राष्ट्र हर तरह से एक आधुनिक समाजवादी देश के निर्माण की दिशा में एक नया सफर शुरू करेगा और दूसरे शताब्दी लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। सीपीसी अपने सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन प्रत्येक पांच साल पर आयोजित करती है, जिस दौरान वह सरकार और पार्टी के कार्य की समीक्षा करती है तथा अगले पांच वर्षों के लिए योजनाओं को मंजूरी देती है।

पार्टी की मौजूदा परंपरा के तहत, नेतृत्व और शीर्ष पदाधिकारी हर 10 साल पर बदले जाते हैं। दस साल का कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त होने वाले अपने पूर्ववर्तियों के उलट शी चिनफिंग (69) को 20वें अधिवेशन में राष्ट्रपति पद पर तीसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी मिलने की व्यापक स्तर पर उम्मीद जताई जा रही है। चिनफिंग इस साल पांच साल का अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले हैं।

श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की राजनीतिक दलों से सर्वदलीय सरकार में शामिल होने की अपील

कोलंबो (एजेंसी)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से निपटने के लिए सभी दलों से सरकार में शामिल होने और 'हस्तक्षेप के औजार' के रूप में इसका (देश का) इस्तेमाल करने से ''मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों'' को रोकने की मंगलवार को अपील की। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका के एक बंदरगाह पर चीन के एक हाईटेक पोत को आने की अनुमति दिये जाने को लेकर कुछ दिन पहले भारत और चीन के बीच जुबानी जंग हुई थी। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की यह टिप्पणी वित्त मंत्री के तौर पर 2022 के लिए उनके द्वारा संशोधित बजट पेश किये जाने के दौरान आयी है। विक्रमसिंघे ने कहा, ''हम अब रिण सहायता पर निर्भर देश नहीं रह सकते हैं। हमारा इस्तेमाल अब मजबूत अर्थव्यवस्था वाले अन्य देशों द्वारा हस्तक्षेप के औजार के रूप में नहीं किया जा सकता।'' चीनी पोत 'युआन वांग5' के श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर आने को लेकर चीन और भारत के बीच जुबानी जंग होने के कुछ दिनों बाद उनकी यह टिप्पणी आई है। उन्होंने कहा, ''यह सब कुछ तभी हासिल किया जा सकता है, जब हम साझा सहमति के साथ एकजुट होकर काम करें। मैं संसद में प्रतिनिधित्व रख रहे सभी दलों को एक सर्वदलीय सरकार में शामिल होने का अपना न्योता दोहराता हूं क्योंकि देश की जरूरतों को प्राथमिकता दिये जाने की जरूरत है।''

करियर के सर्वश्रेष्ठ पांचवें स्थान पर पहुंचे हार्दिक पंड्या

दुबई (एजेंसी)।

भारत के स्टार आलराउंडर हार्दिक पंड्या यहां एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टी20 अंतरराष्ट्रीय आलराउंडर रैंकिंग में आठ पायदान की छलांग से करियर के सर्वश्रेष्ठ पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। हार्दिक ने 25 रन पर तीन विकेट चटकाने के बाद सिर्फ 17 गेंद में नाबाद 33 रन बनाए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। यह दर्शाता है कि आस्ट्रेलिया में आगामी टी20 विश्व कप में भारत के अभियान में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी। एशिया कप में अफगानिस्तान की धमाकेदार शुरुआत ने भी सभी का ध्यान खींचा है।

टीम के खिलाड़ियों को रैंकिंग में फायदा मिला है। आईसीसी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि राशिद खान ने नंबर एक गेंदबाज बनने की ओर कदम बढ़ाए हैं। वह साथी लेग स्पिनरों आदिल राशिद और एडम जंपा को पछाड़कर दो स्थान के फायदे से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 708 अंक हैं। राशिद की नजरें अब बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर तबरेज शम्सी (716) को पछाड़ने पर टिकी हैं लेकिन शीर्ष पर जोश हेजलवुड (792) ने बड़ी बढ़त बना रखी है। राशिद के हमवतन मुजीब उर रहमान (660) ने सात स्थान की बढ़त के साथ शीर्ष-10 में प्रवेश किया है। वह आठवें स्थान पर मौजूद भारत के भुवनेश्वर कुमार (661) से पीछे हैं। भुवनेश्वर ने पाकिस्तान के खिलाफ 26 रन पर चार विकेट चटकाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में कोई नया खिलाड़ी नहीं आया है लेकिन पाकिस्तान के मोहम्मद रिज़वान 796 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और अपने कप्तान बाबर आजम (810) के साथ शीर्ष दो में शामिल हो गए हैं।

अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजाई 23 और 37 रन की दो पारियों के साथ तीन स्थान के फायदे से 14वें स्थान पर हैं। उनके साथी रहमानुल्लाह गुरबाज इस बीच पांच पायदान के फायदे से 29वें स्थान पर पहुंच गए। अन्य दो प्रारूपों में कई फेरबदल हुए। दक्षिण अफ्रीका पर इंग्लैंड की जीत में अहम भूमिका के कारण कप्तान बेन स्टोक्स तीनों टेस्ट रैंकिंग में आगे बढ़ने में सफल रहे। स्टोक्स ने शतक बनाने के अलावा दोनों पारियों में दो-दो विकेट चटकाए। वह बल्लेबाजी रैंकिंग में नौ स्थान ऊपर 18वें, गेंदबाजी रैंकिंग में पांच स्थान आगे 38वें और आलराउंडर सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आलराउंडर की सूची में रविंद्र जडेजा शीर्ष पर कायम हैं। एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष दस में कोई बदलाव नहीं दिखा। आस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला चल रही है। टाउन्सविले में वेस्ले मधवेरे ने अर्धशतक की बदौलत 38 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। जिंबाब्वे के उनके साथी रिचर्ड एनगारवा को भी एक स्थान का फायदा हुआ है।

जापान ओपन : स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत जीते, लक्ष्य सेन बाहर

ओसाका (एजेंसी)।

भारत के स्टार शटलर किदांबी श्रीकांत ने दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी ली जी जिया पर सीधे गेम में शानदार जीत दर्ज की लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन लक्ष्य सेन को जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बुधवार को यहां पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। विश्व के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी श्रीकांत ने पुरुष एकल के 37 मिनट तक चले मैच में पांचवीं वरीयता प्राप्त ली को 22-20, 23-21 से हराया। चार मुकाबलों में मलेशियाई खिलाड़ी पर यह उनकी पहली जीत है।

अल्मोड़ा के रहने वाले 21 वर्षीय खिलाड़ी और 2021 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता सेन पुरुष एकल के मैच में विश्व में 21वें नंबर के स्थानीय खिलाड़ी केंटा निशिमोतो से 21-18, 14-21, 13-21 से हार गए। यह मैच एक घंटे और छह मिनट तक चला। यह उनकी जापानी खिलाड़ी के हाथों दो मुकाबलों में पहली हार है। विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर विश्व रैंकिंग में 26वें नंबर पर पहुंचने वाली एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की तेजी से उभरती पुरुष युगल जोड़ी कोरिया के चोई सोल ग्यू और किम वॉन हो से 21-19, 21-23, 15-21 से हार गई।

जूही देवांगन और वेंकट गौरव प्रसाद की मिश्रित युगल जोड़ी को केवल 23 मिनट में चीनी के झेंग सी वेई और हुआंग या किओंग की शीर्ष वरीय जोड़ी से 11-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत ने गजब का जुझारूपन दिखाया लेकिन बीच में उन्होंने ली को वापसी का भी मौका दिया। एक समय वह 15-11 से आगे थे लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को लगातार तीन अंक बनाने का मौका दिया।

श्रीकांत ने हालांकि इसके बाद पांच अंक बनाकर मजबूत बढ़त हासिल की और फिर पहला गेम अपने नाम किया। ली ने दूसरे गेम में अच्छा खेल दिखाया और शुरू से बढ़त हासिल कर ली। एक समय वह 14-11 से आगे थे लेकिन श्रीकांत ने जल्द ही 18-16 से बढ़त बनाई और 20-18 के स्कोर पर वह मैच जीतने के करीब थे। ली ने हालांकि दो मैच प्वाइंट बचाए और स्वयं गेम प्वाइंट हासिल किया। श्रीकांत ने तीन अंक बनाकर मैच को आगे नहीं खिंचने दिया।

दूसरे पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने पहले गेम में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जल्द ही 7-2 और फिर 15-9 से बढ़त हासिल कर ली। सेन ने पहला गेम आसानी से अपने नाम किया। सेन ने दूसरे गेम में भी अच्छी शुरुआत करके 8-4 से बढ़त हासिल कर ली थी लेकिन इसके बाद वह अपनी लय खो बैठे। निशिमोतो ने इसका पूरा फायदा उठाया और फिर वह भारतीय खिलाड़ी पर हावी हो गए। मंगलवार को एचएस प्रणय ने अपने प्रतिद्वंद्वी हांगकांग के एनजी का लॉन्ग एंगस के मैच के बीच से हट जाने के कारण दूसरे दौर में जगह बनाई थी।

एशिया कपः बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर अफगानिस्तान सुपर चार में

शारजाह (एजेंसी)।

मुजीब उर रहमान और राशिद खान की फिरकी के जादू के बाद नजीबुल्लाह जादरान और इब्राहिम जादरान की नाबाद पारियों से अफगानिस्तान मंगलवार को यहां ग्रुप बी मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत के साथ एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण में जगह बनाने वाली पहली टीम बना। बांग्लादेश के 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने नजीबुल्लाह (17 गेंद में छह छक्कों और एक चौके से नाबाद 43) और इब्राहिम (41 गेंद में चार चौकों से नाबाद 42) के बीच चौथे विकेट की 69 रन की साझेदारी की बदौलत नौ गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 131 रन बनाकर जीत दर्ज की।

नजीबुल्लाह ने मोसादेक हुसैन पर छक्का जड़कर अफगानिस्तान को जीत दिलाई। इससे पहले मुजीब ने 16 जबकि राशिद ने 22 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए जिससे बांग्लादेश की टीम सात विकेट पर 127 रन ही बना सकी। मोसादेक हुसैन (नाबाद 48, 31 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली जबकि महमूदुल्लाह (25) ने उपयोगी योगदान देकर बांग्लादेश को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। इन दोनों ने छठे विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी भी की। लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफगानिस्तान की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही।

रहमानुल्लाह गुरबाज (11) को छह रन के स्कोर पर शाकिब अल हसन (13 रन पर एक विकेट) गेंद पर जीवनदान मिला लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और बांग्लादेश के कप्तान की गेंद पर ही स्टंप हो गए। सलामी बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई (25) ने मेहदी हसन पर दो चौकों के साथ पावर प्ले में टीम का स्कोर एक विकेट पर 29 रन तक पहुंचाया। इब्राहिम ने भी तास्किन अहमद पर चौका जड़ा लेकिन मोसादेक (12 रन पर एक विकेट) ने हजरतुल्लाह को पगबाधा कर दिया।

एशिया कप में उचित योजना से पाकिस्तान को हरा सकता है अफगानिस्तानः असगर

दुबई (एजेंसी)।

बांग्लादेश के खिलाफ शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ अफगानिस्तान ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर एशिया कप के सुपर फोर के लिए क्वालीफाई कर लिया है। नजीबुल्लाह जादरान की 17 गेंदों में 43 रनों की तूफानी पारी ने अफगानिस्तान को जीत दिलाने में मदद की। राशिद खान और मुजीब उर रहमान की वीरता ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को थोड़ा भी शांत नहीं होने दिया और इसके साथ ही नेटिजन्स ने ट्विटर पर कहा कि यह टीम टूर्नामेंट में परेशान कर सकती है और भारत या पाकिस्तान में से किसी को भी हरा सकती है।

अफगानिस्तान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी असगर अफगान ने इस संभावना से इंकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उनके अधिकांश खेल करीब रहे हैं और अब अगर टीम शांत रहती है और एक उचित योजना है तो वे अंततः एशिया कप में पाकिस्तान को हरा सकते हैं। इस 35 वर्षीय ने खिलाड़ी ने कहा, अगर हमारे खिलाड़ी योजना पर टिके रह सकते हैं और शांत रह सकते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान के खिलाफ वास्तव में अच्छा मैच होगा और उम्मीद है कि हम उन्हें हरा भी सकते हैं।

बांग्लादेश के खिलाफ 3-3 विकेट के साथ राशिद और मुजीब हर चर्चा का केंद्र रहे। पावरप्ले से ही मुजीब ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया और तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच को अपने नियंत्रण में ले लिया। बाद में राशिद ने शानदार गेंदबाजी से बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। दोनों की गेंदबाजी को देखकर कई टीमों को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है। यूएई की परिस्थितियां उनकी गेंदबाजी के अनुकूल हैं और इस तरह वे मेगा खिताब के लिए भारत और पाकिस्तान टीम को चुनौती दे सकते हैं।

असगर का मानना है कि भारत को बढ़त मिल सकती है क्योंकि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में राशिद और मुजीब के साथ काफी खेला है। उन्होंने कहा, जो खिलाड़ी उनके खिलाफ काफी खेले, वही उनके खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं। भारतीय खिलाड़ी हमारे गेंदबाजों को अच्छे से खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने आईपीएल में काफी खेला है। इस प्रकार उनके पास उनके बारे में एक विचार है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं जानते कि हमारे गेंदबाजों से कैसे निपटा जाए क्योंकि वे हमारे खिलाफ ज्यादा नहीं खेले।

मार्श चोट के कारण जिंबाब्वे श्रृंखला से बाहर, भारत दौरे के लिए उपलब्ध रहेंगे

मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मिशेल मार्श टखने की मामूली चोट के कारण जिंबाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले एकदिवसीय मैचों से बाहर हो गए हैं लेकिन उनके टी20 विश्व कप से पहले भारत दौरे के लिए फिट होने की संभावना है। 'ईएसपीएनक्रिकइंफो' की रिपोर्ट के अनुसार मार्श की जगह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस को टीम में लिया गया है, जो अभी इंग्लैंड में लंदन स्पिरिट की तरफ से द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार,''मार्श की चोट को टखने की मामूली चोट बताया गया है और टी20 विश्व कप के मद्देनजर यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है।'' मार्श ने जिंबाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में पहले बदलाव के रूप ने गेंदबाजी की थी और उन्होंने छह ओवर में 22 रन देकर एक विकेट लिया था। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए में वह केवल दो रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलिया को अभी जिंबाब्वे के खिलाफ 31 अगस्त और 3 सितंबर को दो वनडे मैच खेलने हैं। इसके बाद उसकी टीम तीन वनडे मैच के लिए न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी। ये मैच छह से 11 सितंबर के बीच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया 20 से 25 सितंबर के बीच होने वाले तीन टी-20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारत का दौरा करेगा। मार्श के इन मैचों के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत, श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाई

टाउन्सविले (ऑस्ट्रेलिया) (एजेंसी)।

मिशेल स्टार्क की अगुवाई में गेंदबाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे को सस्ते में समेट कर दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बुधवार को यहां आठ विकेट से बड़ी जीत दर्ज करके तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 से अजेय बढ़त बनाई। स्टार्क ने 24 रन देकर तीन विकेट लिए और जिंबाब्वे के शीर्ष क्रम को लड़खड़ाने में अहम भूमिका निभाई। जिम्बाब्वे इन शुरुआती झटकों से आखिर तक नहीं कर पाया और उसकी टीम 27.5 ओवर में 96 रन पर आउट हो गई। स्टार्क के अलावा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जंपा ने 21 रन देकर तीन और कैमरन ग्रीन ने सात रन देकर दो विकेट लिए। जिम्बाब्वे की तरफ से सीन विलियम्स ने सर्वाधिक 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 14.4 ओवर में आठ विकेट पर 100 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की। उसकी तरफ से स्टीव स्मिथ ने नाबाद 47 और अलेक्स कैरी ने नाबाद 26 रन बनाए।

डेविड वॉर्नर (13) और कप्तान आरोन फिंच (एक) के जल्दी आउट होने के बाद स्मिथ और कैरी ने तीसरे विकेट के लिए 84 रन की अटूट साझेदारी की। ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला का पहला मैच 99 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से जीता था। तीसरा और अंतिम मैच इसी मैदान पर शनिवार को खेला जाएगा।

दुबई ओपन शतरंज: प्रज्ञानंधा की हकोबयन पर शानदार जीत

दुबई ,यूएई। 22वे दुबई ओपन इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दिन भारत के 17 वर्षीय ग्रांड मास्टर प्रज्ञानंधा नें अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज की ,इसके साथ ही अब वह कजाकिस्तान के रिनात जुमबाएव के साथ 4 अंक बनाने वाले अकेले खिलाड़ी है और अगले राउंड में दोनों की टक्कर टूर्नामेंट महत्वपूर्ण बन गयी है । सफ़ेद मोहरो से खेलते हुए प्रज्ञानंधा नें अर्मेनिया के अरम हकोबयन को सिसिलियन नजडोर्फ ओपनिंग में 48 चालों में पराजित किया इस जीत के साथ अब प्रज्ञानंधा की लाइव रेटिंग 2685 अंको पर पहुँच गयी है और यह साफ है की 2700 अंको को छूने वाले भारत के वह आठवे खिलाड़ी जल्द ही बनेंगे ।

यूएस ओपन2022 : तीन साल बाद न्यूयॉर्क में जीते राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रिंकी को हराया

न्यूयॉर्क। चार बार के यूएस ओपन चैंपियन राफेल नडाल साल 2019 में खिताब जीतने के बाद पहली बार यूएस ओपन में खेल रहे है। राफेल ने 21 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई वाइल्डकार्ड रिंकी हिजिकाता को मंगलवार को शुरुआती दौर में 4-6 6-2 6-3 6-3 से हराया। नडाल ने जीत के बाद कहा कि 'यह एक लंबा इंतजार रहा है। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं वापसी नहीं कर पाउंगा। न्यू यॉर्क में रात में होने वाले मैच निश्चित रूप से सबसे शानदार हैं।' ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी रिंकी को वाइल्ड कार्ड के जरिए टूर्नामेंट में जगह मिली थी। साल 2019 के बाद यह पहला मौका है कि नडाल न्यूयॉर्क में कोई मैच जीते हैं। नडाल ने इस साल ग्रैंड स्लैम में 20वां मैच जीता है। इस मैच के पहले सेट में रिंकी ने जीत हासिल की थी लेकिन दूसरे सेट में नडाल ने लगातार तीन सेट जीतकर मैच खत्म कर दिया। वह अब दूसरे दौर के लिएल तैयार है और उनका सामना इसटी के फैबियो फोगनिनी से होगा।

सैम क्वेरी ने यूएस ओपन के पहले दौर में हार के बाद टेनिस कहा अलविदा

न्यूयॉर्क। कभी नोवाक जोकोविच, एंडी मर्रे और राफेल नडाल पर बड़ी जीत दर्ज करने वाले अमरीका के सैम क्वेरी ने यूएस ओपन के पहले दौर में हारने के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया। कैलिफोर्निया के रहने वाले क्वेरी ने मंगलवार की रात को अपने करियर का आखिरी मैच बेलारूस के इल्या इवाश्का से खेला जिसमें उन्हें 4-6, 6-4, 7-6 (8), 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। क्वेरी की अपने करियर में सर्वोच्च रैंकिंग 11 रही। उन्होंने 2017 में विंबलडन में तत्कालीन नंबर एक खिलाड़ी एंडी मर्रे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इससे एक साल पहले वह नंबर एक जोकोविच को हराकर इस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने 2019 में विंबलडन और 2017 में यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में भी जगह बनाई थी। क्वेरी ने कहा, 'मैंने यह सोचकर ही यूएस ओपन में भाग लिया था। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। पिछले छह सप्ताह काफी अच्छे रहे।'

रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाईटेड छोड़कर नहीं जा रहे, क्लब के मैनेजर ने दिया बयान

मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यूनाईटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने बुधवार को दोहराया कि स्टार फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 'ट्रांसफर विंडो' (खिलाड़ियों की अदला बदली का समय) के अंतिम दिनों में टीम को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्लब के साथ रोनाल्डो के भविष्य को लेकर अनिश्चित तब बढ़ गयी जब मंगलवार को एक और फॉरवर्ड एजाक्स के ब्राजीली अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एंटोनी से करार किया गया। यह पूछने पर कि एंटोनी से करार के बाद रोनाल्डो उनकी योजना का हिस्सा बने रहेंगे तो टेन हैग ने कहा, 'निश्चित रूप से, यह बिलकुल स्पष्ट है।'

भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में पदार्पण करेगी वीएआर तकनीक

नयी दिल्ली, (एजेंसी)।

भारत में होने वाले आगामी अंडर-17 महिला विश्व फुटबॉल कप में वीडियो सहायक रैफरी (वीएआर) तकनीक आयु वर्ग की इस शीर्ष प्रतियोगिता में पदार्पण करेगी। विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) पर लगा 11 दिन का निलंबन हटाकर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के भारत में आयोजन को हरी झंडी दे दी है जो 11 से 30 अक्टूबर तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम, मड़गांव के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा।

फीफा की महिला रैफरी विभाग की प्रमुख कारी सीट्ज ने कहा, ''फीफा अंडर-17 विश्व कप से हमें इस टूर्नामेंट के लिए नियुक्त मैच अधिकारियों के स्तर की महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी मिलेगी।'' फीफा ने बयान में कहा, ''यह प्रतियोगिता नियुक्त किए गए वीएआर के कौशल को परखने और हमारी महिला वीएआर के विकास को जारी रखने का एक और शानदार मौका होगा। यह रोड टू आस्ट्रेलिया/न्यूजीलैंड 2023 परियोजना का हिस्सा है।''

वीएआर तकनीक रैफरी के फैसला लेने की प्रक्रिया में मैच को बदलने वाली चार अहम स्थितियों में मदद करती है जिसमें गोल और गोल से पहले हुए अपराध, पेनल्टी से जुड़े फैसले और पेनल्टी से पहले के अपराध, सीधे लाल कार्ड दिए जाने की घटनाएं और खिलाड़ियों की गलत पहचान शामिल है। पूरे मैच के दौरान वीएआर टीम मैच का रुख बदलने वाली इन चारों परिस्थितियों से जुड़ी स्पष्ट गलतियों पर लगातार नजर रखती है। वीएआर टीम हालांकि स्पष्ट गलतियों या गंभीर घटनाओं से चूकने की स्थिति में ही रैफरी से संपर्क करती है।

भारत में होने वाला अंडर-17 विश्व कप तीसरा फीफा महिला टूर्नामेंट होगा जिसमें वीएआर का इस्तेमाल होगा। इससे पहले कोस्टा रिका में 2022 में महिला अंडर-20 विश्व कप और 2019 में फ्रांस में फीफा महिला विश्व कप में इस तकनीक का इस्तेमाल हो चुका है। भारत में दूसरी बार वीएआर तकनीक इस्तेमाल की जाएगी। इसे पहले इस साल जनवरी-फरवरी में भारत में एएफसी महिला एकशिया कप के दौरान क्वार्टर फाइनल चरण से इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। फीफा की मैच रैफरी समिति ने साथ ही टूर्नामेंट के लिए मैच अधिकारियों की घोषणा की जिसमें 14 महिला रैफरी, 28 महिला सहायक रैफरी, तीन सहायक रैफरी और 16 वीडियो मैच अधिकारी शामिल हैं।

एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) का प्रतिनिधित्व सात सदस्यों संघों के 14 रैफरी, सहायक रैफरी और वीडियो मैच अधिकारी करेंगे। थाईलैंड की पांसा चेसानित, उज्बेकिस्तान की एदिता मिराबिकोवा और कोरिया की ओ हियोन जियोंग को रैफरी चुना गया है। ये तीनों पहली बार फीफा टूर्नामेंट में मुख्य रैफरी होंगी। इन साथ सहायक रैफरी के रूप में थाईलैंड की सुपावान हिंथोंग और नुआनिद डोनजियाग्रीद, आस्ट्रेलिया की योआना चराकतिस, उज्बेकिस्तान की क्रिस्टीना सेरेदा और चीन की फेंग यान और शेई लिजुन जुड़ेंगी। इसके अलावा वीएआर तकनीक में पांच वीडियो अधिकारी होंगे जिसमें यूएई के ओमर मोहम्मद अल अली, सीरिया की हना हताब, थाईलैंड की सिवाकोर्न पू-उदोम और आस्ट्रेलिया की लारा ली और केसी रेईबेल्ट शामिल हैं।

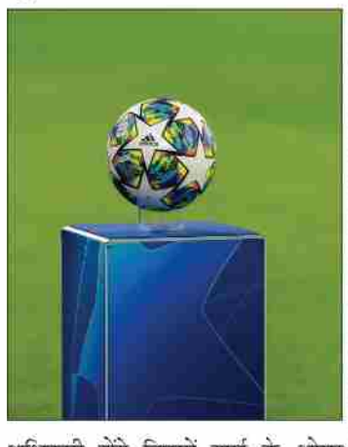

हिमाचल में कांग्रेस की 10 गारंटियां : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटियां देकर चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी बोले: ध्यान से पढ़ें, भविष्य का सोच-समझ कर लें फैसला।

वहीं राहुल गांधी नें 10 गारंटीयो पर जनता से अपील की है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। आने वाले समय में जिस-जिस राज्य में हमारी सरकार बनेगी हम अपने वादे पूरे करेंगे।

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नें कहा, हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान अब कांग्रेस पार्टी की 'गारंटी' है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की भलाई और उनके विकास के मुद्दों पर बात करती है और इस गारंटी कार्ड में भी हमने हिमाचल की जनता के मुद्दों को गांव-गांव जा कर टटोला, स्थानीय लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और फिर उनका हल निकालते हुए ये 'गारंटी कार्ड' तैयार किया है।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें मुख्य रूप से 10 बातों की गारंटी दी जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम, महिलाओं के लिए 1500 रु, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 5 लाख रोजगार, फसलों और फलों के सही दाम, 680 करोड़ रु का स्टार्ट-अप फंड, मोबाइल क्लीनिक, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, कांग्रेस की सरकार हर रोज गाय-भैंस पालकों से 10 लीटर दूध खरीदेगी और 2 रु किलो में गोबर।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया। आने वाले समय में जिस-जिस राज्य में हमारी सरकार बनेगी हम अपने वादे पूरे करेंगे। इस गारंटी कार्ड को ध्यान से पढ़ें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और सोच-समझ कर फैसला करें। हिमाचल की जनता और कांग्रेस पार्टी मिलकर हिमाचल प्रदेश को फिर से आगे बढ़ाएंगे।

दिल्ली के एलजी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले आप विधायकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) के उन नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है, जिन्होंने सक्सेना पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था।

एलजी कार्यालय के सूत्र के अनुसार, आप नेताओं - सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक और जैस्मीन शाह सहित अन्य के खिलाफ उनके द्वारा केवीआईसी अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के लिए मानहानि और भ्रष्टाचार के झूठे आरोपों के लिए कार्रवाई की जाएगी।

आप के इन नेताओं ने हाल ही में दावा किया है कि सक्सेना 2016 में नोटबंदी के दौरान एक घोटाले में शामिल थे, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। सूत्र ने कहा कि सीबीआई पहले ही केवीआईसी के कहने पर मामले की जांच कर चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है।

सूत्र ने कहा कि जिन दो लोगों के बयानों के आधार पर एलजी के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं, जिन्हें सीबीआई ने नोटबंदी के बाद प्रथम दृष्टया केवीआईसी में भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है।

सूत्र के मुताबिक, एलजी ने कहा कि आप अपने व्यापक कुकर्मो से ध्यान हटाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रही है। शिक्षा, शराब और पीडब्ल्यूडी में बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। सूत्र ने कहा कि एलजी ने इन आप नेताओं द्वारा लगाए गए इन खुले तौर पर झूठे, मानहानिकारक और स्पष्ट रूप से विचलित करने वाले आरोपों को गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है।

8 नवंबर, 2016 को केंद्र द्वारा 1000 और 500 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद किए जाने के बाद केवीआईसी ने 9 नवंबर, 2016 को एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 'बिक्री आउटलेट और प्रतिष्ठान तत्काल प्रभाव से 1000 और 500 रुपये के पुराने नोट स्वीकार नहीं करेंगे।'

बाद में पता चला कि कुछ पुराने नोट खादी ग्रामोद्योग भवन (केजीबी), नई दिल्ली के खाते में जमा किए गए थे। जांच और कार्रवाई के लिए मामला केवीआईसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पास भेजा गया था। साथ ही सीबीआई को भी सूचित किया गया और इस सूचना के आधार पर सीबीआई अधिकारियों ने 6 अप्रैल, 2017 को संयुक्त औचक निरीक्षण किया गया।

एक सूत्र के अनुसार, प्रारंभिक जांच के बाद सीवीओ ने चार अधिकारियों - एके गर्ग (प्रबंधक), अजय गुप्ता (बिक्री प्रभारी), संजीव कुमार मलिक (प्रमुख कैशियर), प्रदीप यादव (एलडीसी) के निलंबन और स्थानांतरण की सिफारिश की। 17 अप्रैल, 2017 को इन सभी अधिकारियों को निलंबित कर विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।

सीवीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 10 नवंबर 2016 से 31 दिसंबर 2016 के दौरान दिल्ली में केजीबी बैंक खाते में कुल 22,17,000 रुपये के पुराने नोट जमा किए गए, जिसमें 2140 नोट 500 रुपये के और 1147 नोट 1000 रुपये के थे।

केवीआईसी ने 29 मई, 2017 को सीबीआई को सीवीओ द्वारा की गई शुरुआती जांच और चार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में सूचित किया।

हालांकि, जांच एजेंसी ने पुराने नोटों को जमा करने में केवल दो व्यक्तियों- संजीव मलिक और प्रदीप यादव की संलिप्तता पाई और उनके खिलाफ 10 जुलाई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने पाया कि केजीबी, नई दिल्ली के खाते में केवल 17,07,000 रुपये पुराने नोटों के रूप में जमा किए गए थे।

हालांकि, सीबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि 1000 रुपये और 500 रुपये के मूल्यवर्ग में 22,17,000 रुपये की कुल नकद जमा राशि में से कुल 5,10,000 रुपये की राशि वैध मुद्रा थी, इसलिए राशि को घटाकर 17,07,000 रुपये कर दिया गया।

सूत्र ने कहा कि सीबीआई पहले ही दो आरोपियों संजीव कुमार मलिक और प्रदीप यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और मामला नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है।

सूत्र ने कहा कि आप 1400 करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले सिर्फ 17.07 लाख रुपये का मामला बता रही है, जो कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। इसके लिए उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।

राजनीति का केंद्र बना रायपुर का रिजॉर्ट, आराम फरमा रहे झारखंड के विधायक

रायपुर, 31 अगस्त (एजेन्सी)। झारखंड के विधायकों के पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कोलाहल से दूर नवा रायपुर शहर का मेफेयर रिजॉर्ट राजनीति का केंद्र बन गया है। रिजॉर्ट मंगलवार से एक किले में तब्दील है।

इस रिजॉर्ट में झारखंड से आए 32 विधायक और वरिष्ठ नेता ठहरे हुए हैं तथा बाहर मीडियाकर्मियों तथा जनता का जमावड़ा है, जो इस शहर को पर्यटन की राजनीति का केंद्र बनते देख रहे हैं।

नवा रायपुर अटल नगर स्थित आलीशान मेफेयर रिजॉर्ट की सड़कें आमतौर पर सुनसान रहती हैं। लेकिन, मंगलवार शाम से लक्जरी बसों, मंहगी कारों और नेताओं के काफिले की आवाजाही से इस सड़क पर चहल-पहल काफी बढ़ गई। पल-पल की खबरों के लिए जहां रिजॉर्ट के बाहर पत्रकारों का जमावड़ा है। वहीं कौतुहल के कारण आए नागरिकों की भीड़ ने भी सड़क का सूनापन दूर कर दिया है।

कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ पिछले डेढ़ वर्ष से पर्यटन की राजनीति का केंद्र बन गया है। इस छोटी अवधि में यह तीसरी बार है, जब विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त से बचने के लिए कांग्रेस या उसके सहयोगी दल के विधायकों को यहां ठहराया गया है।

इसी श्रृंखला में एक कड़ी मंगलवार शाम को तब जुड़ गई, जब पड़ोसी राज्य झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने अपने 32 विधायकों को रायपुर के इस प्रसिद्ध रिजॉर्ट में भेज दिया। गठबंधन का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चल रहे राजनीतिक संकट का फायदा उठाकर कथित तौर पर उनके विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर सकती है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार शाम को विधायकों के रिजॉर्ट पहुंचने से पहले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई तथा अगले कुछ दिनों के लिए झारखंड से आए मेहमानों के लिए लगभग सभी 40 कमरे बुक कर लिए गए थे।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि जब विधायक रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे तब छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं रामगोपाल अग्रवाल और गिरीश देवांगन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के 15 और कांग्रेस के 17 विधायक पुलिस के एक काफिले के साथ तीन बसों में सवार होकर रिजॉर्ट तक पहुंचे।

उन्होंने बताया कि विधायकों के साथ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडेय और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी रायपुर पहुंचे हैं।

इस बीच, समाचार संकलन के लिए रिजॉर्ट के करीब जमा हुए कुछ मीडियाकर्मियों और लोगों ने मंगलवार को एक वाहन को देखा जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था और वह रिजॉर्ट की ओर शराब की बोतलें ले जा रही थी।

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, विपक्षी दल भाजपा ने सत्ताधारी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, छत्तीसगढ़ इस तरह के अनैतिक कृत्य के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करेगा।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए! छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू-मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा, इन अनैतिक कार्यों के लिए। छत्तीसगढ़ महतारी (मां) आपको कभी माफ नहीं करेगी।

वीडियो वायरल होने के बाद इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया और कहा कि उनकी पार्टी या सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

वहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को कहा कि खरीद-फरोख्त की आशंका के कारण झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ आए हैं।

कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ नहीं आए हैं। हालांकि, बुधवार शाम तक वह रायपुर पहुंच सकते हैं।

होटल व्यवसाय से जुड़े एक व्यवसायी ने बताया कि मेफेयर गोल्फ रिजॉर्ट के कमरे के किराए के संबंध में ऑनलाइन जानकारी नहीं मिली है, हालांकि इसी तरह की अन्य सुविधा के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में छूट के बाद लगभग 4200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से कमरा लिया जा सकता है।

जबरन वसूली मामले में जैकलिन फर्नांडीस 26 सितंबर को कोर्ट में तलब

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीस को सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कथित जबरन वसूली मामले में 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडीस का नाम लेने के बाद ये समन जारी किया गया है।

ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश परवीन सिंह ने अभिनेत्री को 26 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

हाल ही में ईडी ने जैकलिन की कई फिक्सड डिपोडिट को यह कहते हुए कुर्क कर लिया कि पैसे गलत तरीके से अर्जित किए गए हैं। ईडी ने अभिनेत्री के खिलाफ 17 अगस्त को दूसरा पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी ने जैकलिन की 7.2 करोड़ रुपये की एफडी को अपराध की आय बताते हुए कुर्क कर दिया था।

फरवरी में, ईडी ने चंद्रशेखर की कथित सहयोगी पिंकी ईरानी के खिलाफ अपनी पहली पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड अभिनेत्रियों से मिलवाया था।

चार्जशीट के अनुसार, पिंकी जैकलिन के लिए महंगे उपहार लाती थी जिसका भुगतान चंद्रशेखर करता था।

ईडी ने पिछले साल दिसंबर में इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। चंद्रशेखर ने मॉडलों और बॉलीवुड हस्तियों के लिए गिफ्ट खरीदने पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च किए।

जैकलिन ने चंद्रशेखर से महंगे तोहफे मिलने की बात कबूल की है।

दिल्ली सरकार ने शुरु किया पहला वर्चुअल स्कूल

नई दिल्ली, 31 अगस्त (एजेन्सी)। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली में शारीरिक कक्षाएं लेने में असमर्थ छात्रों के लिए देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया।

केजरीवाल ने लॉन्च करते हुए कहा, 'हमने हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम और कई विशेष स्कूल शुरू किए, साथ ही हम ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बना रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल शुरू किया गया है। आज हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि कई माता-पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, कई बच्चे जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चे इस वर्चुअल स्कूल में पढ़ सकते हैं।

उन्होंने एक डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग में कहा, 'बच्चों को शारीरिक रूप से स्कूल आना चाहिए, लेकिन जो इसे बनाने में असमर्थ हैं, उन्हें यह स्कूल शिक्षा प्रदान करेगा।'

उन्होंने आगे कहा, 'स्कूली शिक्षा मंच में प्रवेश पूरे भारत के छात्रों के लिए खुला होगा और उन्हें कौशल आधारित प्रशिक्षण के साथ नीट, सीयूईटी और जेईई जैसी प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा भी तैयार किया जाएगा।'

कक्षा 9 के लिए 2022-23 के लिए बुधवार से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए देश भर से 13 से 18 साल की उम्र का कोई भी बच्चा आवेदन कर सकता है।

'प्रत्येक बच्चे को एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वह कक्षाओं में भाग ले सकेगा, डिजिटल लाइब्रेरी की सामग्री तक पहुंच सकेगा। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को गूगल और स्कूल नेट इंडिया ने बनाया है। यह एक क्रांतिकारी कदम होगा।'

'एक देश-एक चुनाव' आज वक्त की जरूरत : नकवी

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (एजेन्सी)। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि एक देश-एक चुनाव' आज वक्त की जरूरत है और सभी राजनीतिक दलों को इस दिशा में 'राजनीतिक पूर्वाग्रह' छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में नकवी ने यह भी कहा कि देश को इस महत्वपूर्ण चुनाव सुधार की दिशा में खुली सोच के साथ राजनीतिक हितों से ऊपर, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी होगी।

नकवी ने कहा, देश में हर छह महीने में कहीं न कहीं कोई चुनाव होते हैं और राजनीतिक पार्टियां हर समय में चुनाव मशीन बन जाती हैं। इससे जहां एक तरफ जन धन की बर्बादी होती है, वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है। साथ ही इससे लोगों में चुनावों के प्रति बढ़ती उदासीनता के चलते यह 'लोकतंत्र के पर्व' को फीका बना रहा है।'

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश-एक चुनाव' के लिए कई बार आह्वान कर चुके हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों का रवैया इस विषय पर उदासीन और नकारात्मक रहा है। जनता चाहती है कि लगातार चुनावी चक्रव्यूह के चक्कर से बाहर निकले और एक देश-एक चुनाव' की व्यवस्था लागू हो।''

नकवी के अनुसार, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से ना केवल बेतहाशा जन धन की बर्बादी रुकेगी, वहीं बार-बार चुनावी प्रक्रिया और बंदिशों से विभिन्न विकास कार्यों में जो बाधा होती है वह भी खत्म हो सकेगी।

सीएम योगी ने जाना पूर्वांचल में बाढ़ का हाल, हवाई सर्वेक्षण किया, राहत सामग्री बांटी

गाजीपुर, 31 अगस्त (एजेन्सी)। पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालतों का जायजा लेने गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे।

सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया। इसके बाद पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने सीएम योगी सबसे पहले गाजीपुर पहुंचे। के साथ-साथ उनके बचाव इंतजामों को देखने के लिए सीएम योगी गाजीपुर पहुंचे।

उन्होंने गंगा की बाढ़ का दंश झेल रहे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली के लिए रवाना हो गए। चंदौली के बाद योगी वाराणसी भी जाएंगे। यहां गंगा नदी में घटाव शुरू हो चुका है लेकिन जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है।

पूर्वांचल में मंत्रियों के दौरे के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में दस्तक दी। लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक सीएम ने बाढ़ ग्रसित इलाके जाने और उन क्षेत्रों में कहर ढा रही नदियों का जलस्तर और प्रवाह भी जाना।

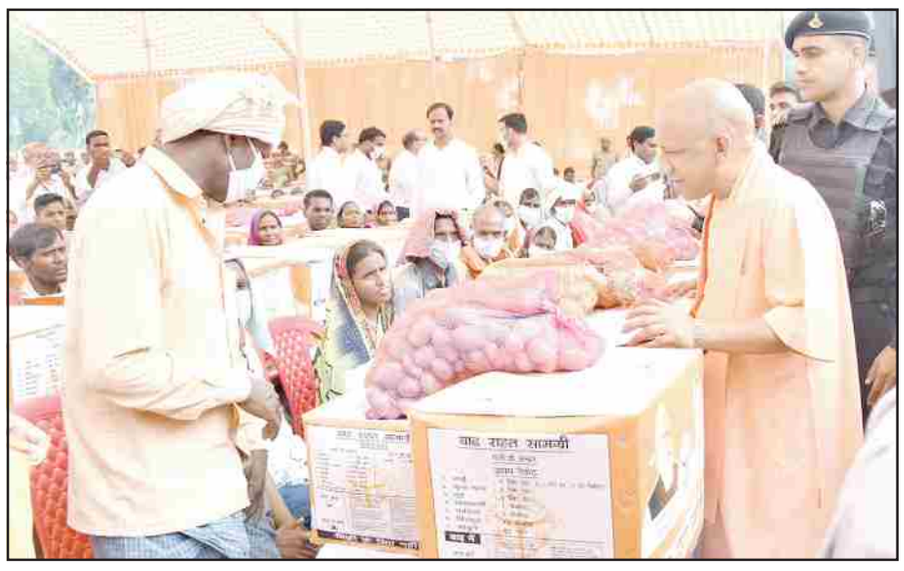

गाजीपुर में गंगा किनारे सीएम का हेलीकॉप्टर ने धीमी रफ्तार से नीचे तक के इलाकों का सर्वे किया। दोपहर तीन बजे सीएम का हेलीकॉप्टर सेमरा, शेरपुर और बलिया सीमाक्षेत्र तक चक्रमण कर अष्ट शहीद इंटर कालेज मैदान पर उतरा।

हेलीपैड पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भाजपा जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह के साथ सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी इंटर कालेज परिसर में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में पहुंचे। यहां पीड़ितों को राहत सामग्री दी।

इसके बाद सेफ हाउस में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

प्रमुख भाजपा नेताओं से अलग-अलग मुलाकात भी की। सीएम के दौरे को लेकर इंतजाम चाक चौबंद रहे और गंगा किनारे में एनडीआरएफ समेत पीएसी और पुलिस टीम तैनात रही।

आजाद के समर्थन में और नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस

श्रीनगर, 31 अगस्त (एजेन्सी)। जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस के एक दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलाम नबी आजाद का समर्थन करने के लिए बुधवार को इस्तीफा दे दिया।

समूह का नेतृत्व करते हुए, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री, पीरजादा सईद ने कहा कि वह उस पार्टी को छोड़ने के लिए दुखी महसूस कर रहे हैं जिसके साथ वह 35 से अधिक वर्षों से जुड़े थे।

सईद ने कहा, 'कांग्रेस आलाकमान की गलत नीतियों के कारण पार्टी सिकुड़ गई है। हमने जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करने और बहुत पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए आजाद साहब से जुड़ने का फैसला किया है।'

इस्तीफा देने वालों में मुहम्मद मुजफ्फर पारे, एक पूर्व विधायक और जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और हाजी अब्दुल गनी खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीनगर शामिल हैं।

मंगलवार को कांग्रेस के उस

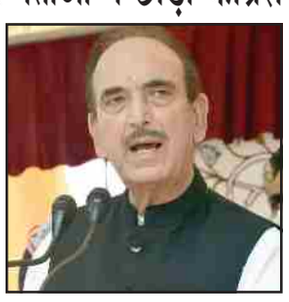

वक्त और बड़ा झटका लगा जब केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री ताराचंद समेत केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस के करीब 64 वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दिया था।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद (73) ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। वह पार्टी से पांच दशक तक जुड़े रहे। उन्होंने दावा किया था कि पार्टी व्यापक रूप से नष्ट हो चुकी है। आजाद ने इसके पूरे परामर्श तंत्र को कथित तौर पर ध्वस्त करने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की थी।

आजाद ने घोषणा की है कि वह जल्द ही वह जम्मू कश्मीर में एक पार्टी गठित करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर की होगी।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक : सत्येन्द्र नाथ सिंह एवं मुद्रक: नूतन वर्मा द्वारा प्राइम प्रिंटर्स, प्रिमुला कॉटेज, चर्च रोड, गंगटोक से मुद्रित एवं रतना निवास, मेट्रो प्वाइंट, नेशनल हाईवे 10, गंगटोक (पूर्व सिक्किम) से प्रकाशित।
सम्पादक - सत्येन्द्र नाथ सिंह, कार्यकारी सम्पादक - अश्विनी आनंद, मोबाइल नं. : 9474355832, 9609024017, फोन नं. : 03592-204174, पोस्टल रजि. सं. : WB/SKM/110/07-09, e-mail ID : anugamini@gmail.com